वर्ष-10//अंक-2//नवंबर 2021

ISSN 2454–5805

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

आदिवासी नृत्य महोत्सव में झूमा सारा जहां

» 6

बारूद के ढेर में राजधानी!

» 8

ऑर्गनिक फूड के पहले स्टोर को सम्मान

» 26

25 हजार करोड़ के 325 प्रोजेक्ट्स से बनेगी राम नगरी

www.aamaadmi.in
www.aamaadmee.com

बेहतर प्राकृतिक जीवन के लिए...

अपनाएं 100% शुद्ध ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स

ORGALIFE®

Eat Organic, Stay Healthy

माउथ फ्रेशनर | पिंक रॉक सॉल्ट | गुड़ | चाय मसाला

MARKETED By : **ORGALIFE FOOD & BEVERAGES (INDIA)**

For Trade Queries/Suggestions +91-9755166633 care@orgalife.in Follow us on

आम आदमी पत्रिका

वर्ष-10//अंक-2//नवंबर 2021

प्रबंध संपादक	: उमेश के बंसी
संपादक	: प्रत्यूष शर्मा
विशेष संवाददाता	: अनुपम सोनी (दिल्ली)
सर्कुलेशन इंचार्ज	: प्रकाश बंसी
रिपोर्टर	: नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर	: प्रशांत पारीक
विडियो एडिटर	: शुभम शर्मा
क्रिएटिव डिजाइनर	: देवेन्द्र देवांगन
मैग्ज़ीन डिज़ाइनर	: युनिक ग्राफिक्स
मार्केटिंग मैनेजर	: किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन	: निरूपमा मिश्रा
अकाउंट असिस्टेंट	: प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर	: योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय

965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन : 0771-4044047
ईमेल : khabar@aamaadmi.in

कार्यालय

प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक

उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

इस अंक में

महंगी स्वास्थ्य सेवा के दौर में एक बड़ा वरदान

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जेनेरिक दवा दुकान की श्रृंखला श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया है। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने की कड़ी में यह एक और नया कदम है। 8

योजनाओं का लाभ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता 10

मंत्री लखमा किस्टाराम में आयोजित सुविधा शिविर में शामिल हुए...

लोग भांजे में देखते हैं प्रभु राम की छवि 12

भगवान श्री राम का भांजा के स्वरूप में गहरा नाता है ...

कुपोषण में कमी लाने वाले राज्यों में अग्रणी 15

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा

38 लाख संरचनाओं का होगा निर्माण 20

392 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है...

अलंकरण पुरस्कार 22

विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले को अलंकरण पुरस्कार दिया गया...

मत्स्य कृषकों बिना ब्याज मिलेगा ऋण 28

कृषि का दर्जा मिलने से पानी और बिजली में भी छूट का लाभ

न्याय योजना से आएगी हरियाली

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

कोई काम तब फायदे का होता है जब उसमें जितना खर्च हो रहा है, उससे ज्यादा दाम पर वह बिके। खेती ऐसा काम नहीं है इसमें किसान जितना पैसे खर्च कर कोई फसल लगाता है। जब बेचता है तो उसे उतना पैसा नहीं मिलता है जितना वह खर्च करता है। इसलिए खेती को घाटे का काम कहा जाता है। भूपेश बघेल सरकार ने खेती को लाभकारी बनाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना बनाई है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में खरीफ की विभिन्न फसलों के लिए 9 हजार प्रति एकड़ व धान के रकबे में अन्य फसल लेने पर 10 हजार रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि दी जाती है।

आमतौर पर समर्थन मूल्य पर किसानो से जो फसल खरीदी जाती है, उसी का दाम उसे सबसे ज्यादा मिलता है। किसान मंडी में बेचने जाते है तो वहां मांग व आपूर्ति के हिसाब से ही उनकी फसल की कीमत तय होती है। उसे अक्सर सही दाम नहीं मिलता है। भूपेश बघेल सरकार ने किसानों को फसल की ज्यादा कीमत देने के लिए राजीव गांधी न्याय योजना बनाई है।

इस योजना के तहत किसानों का धान सरकार केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य पर खरीदती है तथा फसल के हिसाब से किसानों को अलग से प्रति एकड़ 9 व 10 हजार रुपए देती है। इससे किसानों को दूसरे राज्यो के किसानों की तुलना में अपनी फसल का ज्यादा पैसा मिलता है। यहां ज्यादा पैसा मिलता है लेकिन किसान संगठनों के हिसाब से यह पैसा भी किसानों के घाटे को पूरा नहीं करता है।

किसान को प्रति एकड़ लागत मान लिया जाए तीस हजार रुपए प्रति एकड़ आता है तो छत्तीसगढ़ में तो किसानों को 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है, लेकिन दूसरे राज्यों में 1900 से 2000 रुपए ही मिलता है। न्याय योजना से राज्य के किसानों को दूसरे राज्यों के किसानों से छह से सात सौ रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा मिलता है। इस आधार पर सीएम भूपेश बघेल यदि कहते हैं कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत खेती आने वाले दिनों में और लाभकारी होगी तो यह सच है।

यह सच है कि राज्य के किसानों की प्रति एकड़ जितनी लागत आती है, उतना पैसा उन्हें नहीं मिलता है। पर यह भी सच है कि दूसरे राज्यों के किसानों को प्रति एकड़ जितना पैसा मिलता है, उससे ज्यादा पैसा छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किसानों को दे रही है। इससे दूसरे राज्यो के किसानों की तुलना में यहां खेती लाभकारी तो है। हाल ही में सीएम भूपेश बघेल ने संकेत दिया है कि राजीव गांधी न्याय योजना के तहत जो प्रति क्विंटल 2500 रुपए जगह 2800 रुपए दिया जाएगा। यानी अभी किसानों को जितना पैसा मिल रहा है, उससे तीन सौं रुपए प्रति एकड़ ज्यादा मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ में खेती आने वाले दिनों में और लाभकारी तो होगी ही। इससे किसानो को ज्यादा आय होगी वह ज्यादा खर्च करेंगे तो अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी।

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री ने विकास प्रदर्शनी का किया अवलोकन

गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने होंगे साकार : मंत्री रविन्द्र चौबे

> “कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने अपरान्ह साइंस कॉलेज मैदान में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य एवं राज्योत्सव के उपलक्ष्य में विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रदर्शन के लिए लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंत्री रविन्द्र चौबे ने विभागों द्वारा जन सामान्य की जानकारी के लिए विभागीय योजनाओं की प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रचार सामग्री की सराहना की और इसके लिए राज्य शासन के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी। मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि प्रदर्शनी का अवलोकन छत्तीसगढ़ राज्य के विकास की सुखद अनुभूति है। हम सब मिलकर नवा छत्तीसगढ़ गढ़बो के सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं।”

कृषि मंत्री श्री चौबे ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में खेती किसानी को समृद्ध बनाने और राज्य की जलवायु के आधार पर कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के प्रोत्साहन हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उद्यानिकी विभाग की प्रदर्शनी में चाय और कॉफी की जशपुर एवं बस्तर जिले में खेती के प्रदर्शन को उन्होंने सराहा और कहा कि राज्य शासन के इस प्रयास में जशपुर एवं बस्तर अंचल के कृषकों का अच्छा रूझान देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनी स्थल पर कृषि विभाग का डोम इस वर्ष भी मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां मछली पालन, पशुपालन, कृषि आदि के प्रदर्शनी के बीच उद्यानिकी की जीवंत प्रदर्शनी में खासी भीड़ देखने को मिली। छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि जलवायु क्षेत्र के मद्देनजर बने राज्य के नक्शे पर प्रत्येक जिले के मुख्य उत्पाद को दशार्या गया। बागवानी की जीवंत प्रदर्शनी में छोटा तालाब बनाकर मखाना की खेती, ओवरहेड टैंक से ग्रेविटेशनल ड्रिप सिंचाई पद्धति, मल्चिंग में केले की खेती, विभिन्न प्रकार की भाजी, विभिन्न किस्म के आम की खेती, मशरूम उत्पादन, ड्रैगन फ्रूट आदि को दशार्या गया है। उद्यानिकी विभाग के स्टाल में विभिन्न किस्म के पौधे, जशपुर के प्रसिद्ध काजू, मशरूम, उद्यानिकी के प्रसंस्कृत उत्पाद जैसे जैम, आचार, सॉस, नेक्टर आदि स्टॉल पर विक्रय में उपलब्ध हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में राज्य में सिंचाई क्षमता के विस्तार हेतु किए जा रहे कार्यों को मॉडल के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

बारूद के ढेर में राजधानी!

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रायपुर में हर साल बारूद का ढ़ेर लग जाता है। हर साल शहर में ही पटाखे दुकान लगाने की अनुमति जिला प्रशासन दे देता हैं, जबकि शहर से बाहर में दुकानों को लगाने का नियम है।

रायपुर में पटाखों की जांच के नाम पर भी सख्ती नहीं बरती जाती है। हर साल सिर्फ खानापूर्ति के लिए ही पटाखों की जांच होती है। इसी तरह प्रतिबंधित पटाखे भी रखे जाते है। उसकी सप्लाई भी बड़े पैमाने पर होती हैं, जबकि केंद्रीय एजेंसियों ने कई बार रोक लगाने के लिए आदेश जारी किया है, लेकिन पटाखों की खपत हर साल बढ़ते ही जा रही है। जिसकी वजह से हादसों का खतरा भी मंडराते रहता

है। शिकायत भी कई बार जिला प्रशासन में हुई हैं, लेकिन पटाखे दुकान का आबंटन हर बार शहर के बीच में ही होता है। कई बार शिकायतें ऐसी होती है कि कभी भी बड़े हादसे होने के डर से लोग घबराते रहते हैं, लेकिन वहां प्रशासन जांच तक करने के लिए नहीं जाता है। इस वजह से परेशानियां बढ़ती ही जाती है। ऐसा एक बार नहीं, बल्कि कई बार हो चुका है। फिर भी ऐसी सख्ती नहीं होती जो हर साल की जा सके।

सैंपल भी लेकर जांच खानापूर्ति की

शिकायत होने पर सैंपल लेकर जांच तक नहीं की जाती। सैंपल लिए भी गए तो जांच नहीं किया जाता। वहीं अधिकतर लोगों को क्लीन चिट दे दिया जाता है। क्लीन चिट देने के बाद कोई भी तरह की कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ खानापूर्ति की कार्रवाईयां की जाती है।

नियमों का पालन भी नहीं

हर साल क्रय नियमों के तहत पटाखा दुकानों का लाइसेंस दिया जाता हैं। स्थायी और अस्थायी दोनों ही लाइसेंस देने के लिए जगह की जांच-परख की जाती हैं, लेकिन जांच परख होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है। इसलिए नियमों का पालन नहीं होने पर कई बार हादसे भी होते है।

शहर के बीचों-बीच हर साल अनुमति

पहले सुभाष स्टेडियम क्षेत्र में पटाखें दुकानें लगाने की अनुमति दी जाती थी। निगम ही जगह तय कर बारूद के ढ़ेर तैयार करवाता था। अब यहीं चीजें लाखेनगर क्षेत्र में हो रहा है। ईदगाहभाठा मैदान में अनुमति दी जाती है। हर साल वहीं पर अब पटाखे दुकान लगते है। ऐसे 200 दुकानें लगती है। इसमें सबसे ज्यादा लोगों को पार्किंग की समस्या होती थी।

3 लाख की आबादी को खतरा

हर साल तीन लाख से ज्यादा लोगों के जान को खतरे में रखकर पटाखे दुकान लगाने की अनुमति दी जाती है। जहां पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर भी खानापूर्ति होती है। दूसरे प्रदेशों में बड़ी घटनाएं होने के बाद भी सुधार कार्य नहीं किया गया है। एक बार बड़ी दुर्घटना होने के बाद सिर्फ कागजों में ही जांच होती है, कार्रवाई नहीं।

नियम-कायदे सबकुछ ताक पर

पटाखा दुकान लगाने के लिए नियम कई सख्त हैं, लेकिन नियम-कायदों को ताक पर ही रखा जाता है। कई ऐसे बिंदु हैं, जिसका पालन किए बिना ही अनुमति दे दी जाती हैं, जबकि वेरिफिकेशन किया जाता है। फिर भी कोई ऐसा करता नहीं है। जिसकी वजह से लोगों को हर साल परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

दुकान संचालक करते है बारूद स्टॉक

शहरी क्षेत्रों में जब लाइसेंस बांट दिए जाते हैं तो दुकान संचालक भी बारूद स्टॉक करने में देरी नहीं करते है। वहीं त्योहार के पहले ही भारी मात्रा में बारूद स्टॉक किया जाता है। इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता हैं, लेकिन यह जानकारी जिम्मेदारों को होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते है।

बड़े दुकानों में बड़ा स्टॉक

शहर के बड़े दुकानों में बड़ा स्टॉक किया जाता है। इस स्टॉक की वजह से शहर में बारूद का ढ़ेर बढ़ जाता है। जिसकी कोई भी जानकारी जिम्मेदारों को नहीं होने का दावा किया जाता हैं, पर सबकुछ पता होता है। क्योंकि इस मामले में पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती और न ही जिला प्रशासन करता है।

जेनेरिक मेडिसिन: महंगी स्वास्थ्य सेवा के दौर में एक बड़ा वरदान

सस्ती दवाईयों से गरीब और कमजोर परिवारों को मिलेगी राहत

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जेनेरिक दवा दुकान की श्रृंखला श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया है। राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा को मजबूत करने की कड़ी में यह एक और नया कदम है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व मे स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन भी किया जा रहा है, जिसका लाभ राज्य के सभी लोग उठा रहे हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य को बेहतर करने हाट बाजार क्लीनिक योजना तथा शहरी क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं से लोगों को स्वास्थ्य सुविधायें आसानी से मिल रही हैं जिससे लोग बेहद खुश हैं। इन योजनाओं से राज्य में ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।

श्री धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ती दवाईयां उपलब्ध कराना है । दवा बाजार में दो तरह की दवायें मिलती हैं एक ब्रांडेड और दूसरी जेनेरिक। जेनेरिक नाम दवाओं के रासायनिक नाम होते है। जो उसके केमिकल कंपोजिशन के आधार पर दिया जाता है। जेनेरिक दवा के फॉमुर्लेशन पर तो पेटेंट हो सकता है किन्तु उसके एक्टिव कंपोनेंट पर पेटेंट नहीं होता। इसी कारण जेनेरिक दवाएं बिना किसी पेटेंट के बनायी जाती है। इसलिए ये ब्रांडेड दवाओं से सस्ती होती हैं। उदाहरण के तौर पर बुखार के लिए पैरासिटामोल की दवा दी जाती है, इसी पैरासिटामोल घटक को उपयोग में लाते हुए इसकी ब्रांडिंग करके विभिन्न कंपनियां इसे महंगे दामो पर बेचती है। सरकार महंगी ब्रांडेड दवाओं की जगह सस्ती जेनेरिक दवाओं को सरकारी मेडिकल स्टोर के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रही है। ये जेनेरिक दवाईयां गुणवत्ता में किसी भी प्रकार के ब्राण्डेड दवाईयों से कम नहीं होती । यह उतनी ही असरकारक है, जितनी कि ब्राण्डेड दवाईयाँ। गुणवत्ता मानकों की सभी प्रक्रियाओं से गुजारने के पश्चात ही जेनेरिक दवाईयों को बाजार में उतारा जाता है। उनकी मात्रा (डोज), उनके साइड-इफेक्ट आदि सभी ब्रांडेड दवाओं के जैसे ही होते हैं अंतर केवल नाम का होता है। संपूर्ण विश्व में किसी भी दवा का जेनेरिक नाम एक ही होता है। बड़ी -बड़ी कंपनियां भी जेनेरिक दवाईयों का निर्माण करती हैं परंतु ब्रांडिंग न होने और विज्ञापन के अभाव में लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हो पाते हैं। मेडिकल स्टोर संचालक भी ज्यादा लाभ के चक्कर में सिर्फ ब्रांडेड दवाईयां ही बेचते हैं। इस कारण से आम लोगों तक जेनेरिक दवाईयों की पहुंच नहीं हो पाती । परंतु अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों सेये सस्ती दवाईयां लोगों को सुलभ करायी जा रही है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार की जेनेरिक दवाईयां तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य है। इसके अलावा वन विभाग के संजीवनी के उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन उत्पाद और शिशु आहार आदि का भी विक्रय इन मेडिकल स्टोरों में किया जा रहा है। राज्य के वनवासियों द्वारा तैयार किये गये आर्गेनिक उत्पादों (संजीवनी के उत्पादों) का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की अपील भी की गई है, जिससे आदिवासी लोगों के प्रयास को भी बढ़ावा मिल सके ।

इस योजना के शुरू हो जाने से बुखार में उपयोगी पैरासिटामॉल श्री धनवंतरी मेडिकल स्टोर से अब सिर्फ तीन रूपए 88 पैसे में उपलब्ध होगी जो कि बाजार में दस रूपए में आती है। इसी प्रकार शारीरिक कमजोरी में काम आने वाले 169 रूपए का मल्टी विटामिन सीरप सिर्फ 64 रूपए में मिलेगा। उल्टी-दस्त होने पर काम आने वाले 18 रूपए का ओंारएस सिर्फ सात रूपए में जनता को उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना से आम नागरिकों विशेषकर गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों पर दवाईयों में होने वाले खर्च का बोझ कम होगा तथा उन्हें आधे से कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता की दवाईयां प्राप्त हो सकेंगी।

श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स को लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। मेडिकल स्टोर में दवा लेने आये महासमुंद के राजेश कुमार ने कहा कि पहले दिन उन्हें खरीदी पर 600 रूपए की बचत हुई । 1000 रुपए में आने वाली उनकी दवाई के बदले जेनेरिक मेडिसिन सिर्फ 400 रुपए मे आ गयी। बिलासपुर के नूतन चौक स्थित धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की ग्राहक सुश्री मीना अंगुरिया बीपी एवं हाई कोलेस्ट्राल की मरीज है। सुश्री अंगुरिया ने बताया कि वे हर महीने 3700 रूपए की दवाई खरीदती है। आज इस मेडिकल स्टोर में उन्हें यह दवाईयां 1200 रूपए में मिली। इसी प्रकार श्री अश्वनी कुमार तिवारी ने बताया कि उनकी पत्नी श्रीमती गीता तिवारी कैंसर की मरीज है। हर माह उनकी दवाईयों पर 8-10 हजार खर्च होता है। उन्हें इस मेडिकल स्टोर में 1460 रूपए की दवा 360 रूपए में मिली। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ गरीब व्यक्तियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है।

अंबिकापुर निवासी श्री रमेश पटेल ने बताया कि वे हर माह बीपी की दवाई लेते है। दवाईयां सस्ती होने के कारण अब वे इस मेडिकल स्टोर से ही दवाईयां खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि योजना का उन्हें काफी दिनों से इंतजार था। रायपुर के समता कालोनी निवासी सुश्री नेहा प्रधान ने बताया कि उन्हें एलर्जी की 45 रुपये की दवा 16 रुपये में मिली और पूरी दवा जो अन्य दुकान में 550 रुपए की आती , वह सिर्फ 236 रूपए में मिली। श्री एस के बनर्जी ने कहा कि शहर के मध्य में यह दुकान शुरू करने से लोगों केा काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि वे प्रतिमाह लगभग 2 हजार रूपए की दवाई खरीदते है। अब उन्हें इस जेनेरिक मेडिकल स्टोर से यह दवाई रियायती दर में मिल सकेगी । उन्होंन कहा कि सरकार के इस प्रयास से निश्चय ही सभी वर्गों के लोग लाभान्वित होंगे और आमजनों का दवाओं में होने वाले खर्च में काफी कमी आयेगी।

शासन द्वारा शुरूअ ाती चरण में राज्य के 25 जिलों में 84 मेडिकल स्टोर का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत मेडिकल स्टोर में जेनेरिक दवाईयां 50 से 70 प्रतिशत कम कीमत पर उपलब्ध होंगी । शासन की यह पहल महंगी होती जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बीच आम आदमी को काफी राहत पहुंचाने वाली है। प्रथम चरण में दुर्ग जिले में 15, जांजगीर-चांपा जिले में 15, धमतरी, कोरबा और रायगढ़ जिले में 6-6, राजनांदगांव में 5, बिलासपुर, कोण्डागांव, सुकमा और बीजापुर जिले में 3-3, रायपुर, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सूरजपुर और जशपुर जिले में 2-2, महासमुंद, बलौदाबाजार-भाटापारा, गरियाबंद, बेमेतरा, कबीरधाम, सरगुजा, बलरामपुर-रामानुजगंज, बस्तर, नारायणपुर, कांकेर और दंतेवाड़ा जिले में 1-1 मेडिकल स्टोर खोला गया है।

शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

उद्योग मंत्री कवासी लखमा

मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले के प्रवास के दौरान सुदूर वनांचल ग्राम पंचायत किस्टाराम में आयोजित सुविधा शिविर में शामिल हुए। लखमा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दूरस्थ क्षेत्र में सुविधा शिविर का संचालन कर ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं और शासकीय योजनाओं का लाभ प्रदाय करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुविधा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में अंदरूनी क्षेत्रों के ग्रामीणों का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेंशन पंजीयन, स्वास्थ्य कार्ड आदि अब सहजता से बनने लगा है। मंत्री ने कहा कि आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता से कार्य करते हुए जिला प्रशासन ने उमदा कार्य किया है। इसी का परिणाम है कि लगभग 20 हजार ग्रामीणों को इन सुविधा शिविर से लाभान्वित किया गया है।

उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री बघेल के मार्गदर्शन में जिले में विकास कार्यों का विस्तार तेजी से हो रहा है और बस्तर का आदिवासी समुदाय सरकार पर भरोसा करने लगा है। वर्षों से कई क्षेत्र सड़कविहीन और अविद्युतीकृत थे, आज वहाँ चमचमाती सड़के है, विद्युत विस्तार है। सुकमा जिलेवासियों के लिए यह सरकार नए सवेरे की तरह है जिसने आदिवासी जन सामान्य के जीवन में रोशनी लाई है। जिले के कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच नही थी, आज उन क्षेत्र के ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। माताओं तथा छोटे बच्चों को सुपोषित आहार प्रदान करने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र का संचालन, अंदरुनी क्षेत्रों के बच्चों को स्कूली शिक्षा सुलभ करने, वर्षो से बन्द पड़े स्कूलों का पुनः संचालन शिक्षादूत के माध्यम से किया जा रहा है, वहीं संवेदनशील क्षेत्रों जैसे जगरगुण्डा, भेज्जी में स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। मंत्री श्री लखमा ने अधिकारियों को आगामी दिवसों में ग्राम पंचायत वार सुविधा शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं, ताकि प्रत्येक पंचायत में शत प्रतिशत व्यक्तियों को लाभ मिले। इस दौरान बीजापुर विधायक विक्रम शाह मण्डावी, सुकमा नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष जगन्नाथ साहू, सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

गांव, गरीब और किसानों की हितैषी है छत्तीसगढ़ सरकार : मंत्री डॉ. डहरिया

नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा श्रम मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया आरंग विधानसभा अंतर्गत नवा रायपुर के ग्राम राखी में आयोजित सरपंच संघ मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने नवा रायपुर अंतर्गत 41 ग्रामपंचायतों में विकास कार्यों के लिए 4 करोड़ 10 लाख की राशि की स्वीकृति में विशेष पहल करने पर मंत्री डॉ डहरिया का भव्य सम्मान किया।

मंत्री डॉ. डहरिया ने इस अवसर पर सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी निर्वाचित और बहुत ही सम्मानित जनप्रतिनिधि है। आप सभी को ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता के साथ कार्य करते हुए गाँव के विकास के लिए पंचायतों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार द्वारा गाँव के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। यह गांव, गरीब और किसानों की सरकार है और इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है।

मंत्री डॉ. डहरिया ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को लाभान्वित करने के साथ प्रदेश में किसानों का सिंचाई कर माफ कर कर्जमाफी की गई और बिजली बिल हाफ कर लोगों को राहत पहुचाया गया है। गरीब परिवारों को 1 रुपए किलो में चावल प्रदान करने के साथ पशुपालकों से 2 रुपए किलों में गोबर भी खरीदा जा रहा है। प्रदेश के भूमिहीन किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए और सूखा प्रभावित किसानों को 9 हजार रुपए प्रति एकड़ देने का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार किसान हितैषी गाँव, गरीब और मजदूरों की सरकार है। शिक्षा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ बेरोजगारों को नौकरी देने की दिशा में भी सरकार द्वारा लगातार कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने स्व-सहायता समूह के 12 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के कर्ज को भी माफ किया है। मंत्री डॉ. डहरिया ने कहा कि नवा रायपुर अंतर्गत जो भी समस्याएं हैं, उसे निराकरण करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने यहां साहू समाज, धीवर समाज और धोबी समाज के लिए सामुदायिक भवन हेतु राशि की घोषणा की।

लोग भांजे में देखते हैं प्रभु राम की छवि

छत्तीसगढ़ की अस्मिता के प्रतीक माता कौशल्या के पुत्र भगवान श्री राम का भांजा के स्वरूप में गहरा नाता है। इसका जीता-जागता उदाहरण है, छत्तीसगढ़ में सभी जाति समुदाय के लोग बहन के पुत्र को भगवान के प्रतिरूप अर्थात भांजा मानकर उनका चरण पखारते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रभु श्रीराम से कामना करते हैं। यह और भी प्रबल तब होता है, जब गांव-शहर-कस्बा कहीं भी हो कोई भी जाति अथवा समुदाय के हो मांमा-भांजा के बीच के रिश्ते को पूरी आत्मीयता के साथ निभाया जाता है। मांमा के साथ किसी भांजे का यह रिश्ता कई बार माता-पिता के लिए पुत्र से भी ज्यादा घनिष्ठ स्वरूप में दिखाई पड़ता है।

त्रेतायुग में जब छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कोसल व दण्डकारण्य के नाम से विख्यात था, तब कोसल नरेश भानुमंत थे। वाल्मिकी रामायण के अनुसार अयोध्यापति युवराज दशरथ के राज्याभिषेक के अवसर पर कोसल नरेश भानुमंत को भी अयोध्या आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर कोसल नरेश की पुत्री एवं राजकन्या भानुमति भी अयोध्या गई हुई थी। युवराज दशरथ कोसल राजकन्या भानुमति के सुंदर और सौम्य रूप को देखकर मोहित हो गए और कोसल नरेश महाराज भानुमंत से विवाह का प्रस्वाव रखा। युवराज दशरथ और कोसल की राजकन्या भानुमति का वैवाहिक संबंध हुआ। शादी के बाद कोसल क्षेत्र की राजकुमारी होने की वजह से भानुमति को कौशल्या कहा जाने लगा। अयोध्या की रानी इसी कौशल्या की कोख से मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। तभी ममतामयी माता कौशल्या को

तत्कालीन कोसल राज्य के लोग बहन मानकर अपने बहन के पुत्र भगवान श्री राम को प्रतीक मानकर भांजा मानते है और उनका पैर छूकर आशीर्वाद लेते है।

कालांतर छत्तीसगढ में स्मृतिशेष आठवी-नौंवी सदी में निर्मित माता कौशल्या का भव्य मंदिर राजधानी रायपुर से 27 किलोमीटर दूर आरंग विकासखण्ड के ग्राम चन्दखुरी में स्थित है। चंदखुरी भी रामायण से छत्तीसगढ़ को सीधे जोड़ता है। रामायण के बालकांड के सर्ग 13 श्लोक 26 में आरंग विकासखंड के तहत आने वाले गांव चंदखुरी का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि चन्दखुरी सैकड़ों साल पहले चन्द्रपुरी अर्थात देवताओं की नगरी के नाम से जानी जाती थी। समय के साथ चन्द्रपुरी, चन्द्रखुरी हो गया जो चन्द्रपुरी का अपभ्रंश है। पौराणिक दृष्टि से इस मंदिर का अवशेष सोमवंशी कालीन आठवी-नौंवी शताब्दी के माने जाते है। इसके अलावा छत्तीसगढी संस्कृति में राम का नाम रचे-बसे है। तभी तो जब एक दूसरे से मिलते समय चाहे रिश्ते-नाते हो अथवा अपरिचित राम-राम कका, राम-राम काकी, राम-राम भैइया जैसे उच्चारण से अभिवादन आम तौर पर देखने सुनने को मिल ही जाता है। छत्तीसगढ़ के ग्राम चन्दखुरी की पावन भूमि में प्रभु श्रीराम की जननी माता कौशल्या का दुर्लभ मंदिर देश और दुनिया में एक मात्र मंदिर है। यह छत्तीसगढ़ की गौरवपूर्ण अस्मिता का प्रतीक है। प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरते इस मंदिर के गर्भ गृह में माता कौशल्या की गोद में बालरूप में

प्रभु श्रीराम जी की वात्सल्य प्रतिमा श्रद्धालुओं एवं भक्तों के मन को सहज ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। वहीं पूर्वी छत्तीसगढ़ के महानदी, जोंक नदी और शिवनाथ नदी के संगम स्थल शिवरीनारायण क्षेत्र में रामनामी समुदाय में भगवान श्री राम के प्रति अकूत प्रेम एवं अराधना को परिलक्षित करता है।

स्मरणीय तथ्य है कि छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम नाम दक्षिण कोसल था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग दण्डकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यह क्षेत्र उन दिनों दक्षिणापथ कहलाता था। शोधकताओं द्वारा वनवास काल में प्रभु श्री राम चन्द्र जी के यहां आने का प्रमाण मिलता है। शोधकताओं के शोध किताबों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभु श्रीराम ने अपने वनवास काल के 14 वर्षों में से लगभग 10 वर्ष से अधिक समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया था। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में देवी सीता की व्यथा, दण्डकारण्य की भौगोलिकता और वनस्पतियों के वर्णन भी मिलते हैं। माना जाता है कि भगवान श्रीराम ने उत्तर भारत से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने और यहां के विभिन्न स्थानों पर चौमासा व्यतीत करने के बाद दक्षिण भारत में प्रवेश किया था। इसलिए छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ भी कहा जाता है। भगवान श्री रामजी के इन्हीं स्मरणीय तथ्यों और आगमन को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ ने श्री राम के यात्रा पथ को एवं जहां-जहां भगवान श्री राम, भगवान श्री लक्ष्मण और माता सीता ने समय व्यतीत किया है, जिन-जिन स्थानों पर उन्होंने आाराम किया पूजा-अर्चना की उन यादों को सहेजकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चन्दखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर से प्रारंभ कर राम-वन-गमन-पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया है।इससे निश्चित ही देशवासियों की आस्था का सम्मान बढ़ेगा। यह भूपेश सरकार का एक बड़ा उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कदम हैं।

राम-वन-गमन-पथ के निर्माण से निश्चित ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिलेगी। वहीं राम वन गमन परिपथ को एक पर्यटन सर्किट के तौर पर विकसित किए जाने का निर्णय रोजगार मुहैया कराने की दिशा में भी एक कारगर प्रयास होगा। विभिन्न शोध प्रकाशनों के अनुसार प्रभु श्रीराम ने छत्तीसगढ़ में वनगमन के दौरान लगभग 75 स्थलों का भ्रमण किया। जिसमें से 51 स्थल ऐसे हैं, जहां श्री राम ने भ्रमण के दौरान रूककर कुछ समय बिताया था। राम वन गमन पथ में आने वाले छत्तीसगढ़ के नौ महत्वपूर्ण स्थलों सीतामढ़ी-हरचौका (कोरिया), रामगढ़

(अम्बिकापुर) , शिवरीनारायण (जांजगीर-चांपा), तुरतुरिया (बलौदाबाजार), चंदखुरी (रायपुर), राजिम (गरियाबंद), सिहावा-सप्त ऋषि आश्रम (धमतरी) और जगदलपुर (बस्तर) और रामाराम (सुकमा) सहित उन इक्यांवन स्थलों को चिन्हांकित कर विकसित किया जा रहा है। प्रथम चरण में इन नौ महत्वपूर्ण स्थलों को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने 137 करोड़ रूपए का ह्यकान्सेप्ट-प्लानह्य तैयार किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप माता कौशल्या मंदिर के मूलस्वरूप को यथावत रखते हुए भव्य और आर्कषक मंदिर के निर्माण किया गया है। वहीं इस क्षेत्र में सौन्दर्यीकरण का काम भी पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही भगवान श्री राम का 51 फीट ऊंचा भव्य एवं आकर्षक प्रतिमा का निर्माण किया गया है। जिसका अनावरण मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल करेंगे। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के लिए राज्य शासन द्वारा गत वर्ष पांच करोड़ रूपए और इस वर्ष 10 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया था। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने और भव्य राम मंदिर निर्माण शिलान्यास के साथ ही अब छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पर्यटन परिपथ के निर्माण से छत्तीसगढ़ की देश भर में खास पहचान बनेगी। भगवान श्रीराम की माता कौशल्या मंदिर के साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरिया से बस्तर के अंतिम छोर तक राम वन गमन पर्यटन परिपथ का विकास होगा। इससे प्रदेश के पर्यटन का भी तेजी से विकास होगा।

बेस्ट आर्गेनिक फूड का मिला पुरस्कार

सीएम को एमडी ने किया ऑर्गनिक प्रोडक्ट भेंट

ऑर्गनिक फूड के पहले स्टोर को मिला सीएम के हाथों सम्मान

प्रदेश की राजधानी रायपुर में सबसे बड़े आर्गेनिक फूड स्टोर को सम्मान से नवाजा गया है। सीएम भूपेश बघेल ने एक निजी कार्यक्रम में आर्गेनिक फूड स्टोर की सरहाना करते हुए सम्मानित किया। ऑर्गनलाइफ स्टोर सबसे बेहतर प्रोडक्ट देने के लिए तत्पर है। साथ ही लोगों के सेहत के लिए भी ऑर्गनलाइफ के प्रोडक्ट फायदेमंद है।

दरअसल, वीडब्ल्यू केन्यान होटल में न्यूज 18 ग्रुप की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बेस्ट आर्गेनिक प्रोडक्ट का ऐलान किया गया। जिसमें कंपनी के एमडी उमेश बंशी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। बता दें कि वीआईपी रोड राम मंदिर के सामने पहली आर्गेनिक स्टोर है। जहां पर लोग आर्गेनिक प्रोडक्ट की खरीदी के लिए पहुंचते है। इसकी डिमांड भी अच्छी-खासी है। आर्गेनिक ब्रांड का बाजार भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। खासकर दीपावली के मौके पर ऐसे ब्रांड में अच्छी बिक्री की संभावना है। यहां कई प्रोडक्ट की बिक्री तेजी के साथ हो रही है। ऑर्गनिक प्रोडक्ट की प्रदर्शनी भी समय-समय पर की जाती है। इससे लोगो भी काफी पसंद करते है और तेजी के साथ खरीदी भी करते है।

सीएम को प्रोडक्ट भी भेंट किये

कार्यक्रम के दौरान सीएम को ऑर्गनलाइफ स्टोर के एमडी ने ऑर्गनिक प्रोडक्ट भेंट की। इस दौरान सीएम ने प्रोडक्ट की जानकारी भी ली। इसके अलावा प्रोडक्ट को काफी सराहा भी।

ढाई साल में करीब डेढ़ लाख बच्चे कुपोषण मुक्त

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का मिलने लगा अच्छा प्रतिसाद

छत्तीसगढ़ कुपोषण में कमी लाने वाले राज्यों में अग्रणी

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुपोषण मुक्ति की पहल पर छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से शुरू हुए प्रदेशव्यापी मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का अच्छा प्रतिसाद मिलने लगा है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के साथ विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान और समन्वित प्रयास से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है।

प्रदेश में वजन त्यौहार जुलाई 2021 के अनुसार राज्य में केवल 18.84 प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। यदि एनएफएचएस-4 से तुलना करते हैं तो कुपोषण में छत्तीसगढ़ में लगभग 18.86 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। यदि अन्य राज्यों से तुलना करते हैं तो देश के अन्य 21 राज्यों में जहां एनएफएचएस-5 का डाटा जारी किया गया है वहां कुपोषण के स्तर में बढ़ोत्तरी हुई है। आंकड़े नेट पर उपलब्ध है।

गौरतलब है कि एनएफएचएस-4 जो कि वर्ष 2015-16 में जारी हुआ था, उसमें छत्तीसगढ़ में कुपोषण 37.7 प्रतिशत पाई गयी थी तथा राष्ट्रीय औसत 35.7 था। वर्ष 2015-16 के पश्चात राज्य सरकार एवं महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं कायर्क्रमों के माध्यम से बच्चों में कुपोषण कम करने का प्रयास किया गया। अभी जुलाई 2021 में 07 जुलाई से 16 जुलाई 2021 के मध्य वजन त्यौहार का आयोजन किया गया। इस अवधि में लगभग 22 लाख बच्चों का वजन लिया जा कर कुपोषण के स्तर का आंकलन किया गया है। यह एक रियलटाईम डाटा है तथा पारदर्शी तरीके से वजन लिया जा कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा ही एप्प में एंट्री की गई ताकि डाटा की गुणवत्ता प्रभावित न हो। इस अवधि में डाटा की गुणवत्ता परीक्षण के लिए बाह्य एजेंसी की सेवाएं ली गई थी अर्थात वजन त्यौहार का डाटा प्रमाणित डाटा है।

छत्तीसगढ़ में जनवरी 2019 की स्थिति में चिन्हांकित कुपोषित बच्चों की संख्या 4 लाख 33 हजार 541 थी, इनमें से मई 2021 की स्थिति में लगभग एक तिहाई 32 प्रतिशत अर्थात एक लाख 40 हजार 556 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही प्रदेश में कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है, इसका श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है।

आदिवासी नृत्य महोत्सव में झूमा सारा जहां

जनजातीय संस्कृति को सहेजने और उसे आगे बढ़ाने का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का काम मील का पत्थर साबित होगा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भूपेश बघेल ने दीप प्रज्जवलित कर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का किया शुभारंभ

आदिवासियों का वैश्विक मंच बना छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

27 राज्य, 6 केन्द्रशासित प्रदेश और 07 देशों के 1500 से अधिक कलाकार हुए शामिल

विभिन्न देशों एवं राज्यों के नर्तक दलों के कलाकारों ने किया आकर्षक मार्चपास्ट

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य, आदिवासियों की संस्कृति को सहेजने, संवारने और आगे बढ़ाने के लिए अभिनव कार्य कर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह सिर्फ राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय वर्ग का सम्मान है। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग, वर्षों से शोषित रहा है, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा रहा है। उसे आगे बढ़ाने के लिए यह भव्य आयोजन पूरे देश के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि यदि हम सब चाहे तो यह जनजातीय वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, आगे बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जनजातीय वर्ग के प्रति यह प्रयास मील का पत्थर साबित होगा।

रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर से 1 नवम्बर तक आयोजित होने वाले इस ह्यराष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सवह्न और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में देश के 27 राज्यों और 6 केन्द्रशासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 07 देशों- एस्वातीनी, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, यूगांडा, माली और फिलिस्तीन से आए लगभग 1500 कलाकार भाग ले रहे हैं।

मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन ने आगे कहा कि आज भौतिकवादी युग में जनजातीय समाज अपनी सभ्यता, संस्कृति को बचाने में लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस कार्यक्रम को देखकर यह महसूस हो रहा है कि इससे जनजाति वर्ग में आशा जगेगी। इससे उन्हें ताकत और ऊर्जा मिलेगी, वह अपनी संस्कृति और सभ्यता को अक्षुण्ण रखेंगे। उन्होंने कहा कि यहां आदिवासियों की कला, संस्कृति के साथ-साथ उनके उत्पाद के प्रदर्शन एवं विक्रय का मेला लगा है। श्री सोरेन ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की बेहतरी और उनके कल्याण के लिए संचालित योजनाओं का अध्ययन करते हैं और अपने राज्य में भी बदलाव की कोशिश करते हैं। उन्होंने जल-जंगल-जमीन जनजातीय समाज की आत्मा है। खेत-खलिहान, पशुधन और वनोपज इनकी सम्पत्ति है। छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी और वनवासियों को तेंदूपत्ता से लेकर लघु वनोपजों का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ की और कहा कि उनका यह मानना है कि जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा, तब तक शहर, प्रदेश और देश समृद्ध नहीं होगा। जनजातीय समुदाय की क्रय शक्ति बढ़े, इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर राज्य के सभी वर्ग एवं समाज के देवी-देवताओं को नमन करते हुए कहा कि अनेकता में एकता हमारी ताकत और पहचान है। उन्होंने कहा कि इसे जोड़ने एवं संजोने के लिए विश्व के आदिवासियों को एक मंच पर लाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है, ताकि वह संस्कृति को, अपनी ताकत को जाने और आगे बढ़े। छत्तीसगढ़ आज आदिवासियों का वैश्विक मंच के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सफलता मिली है। यह राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का द्वितीय आयोजन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में 42 जनजातियां और 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती है। इनकी जनसंख्या राज्य की कुल आबादी की एक-तिहाई है। सभी जनजातियों की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। उनकी बोली, उत्सव, नृत्य, देवी-देवता भी अलग-अलग है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से जनजातियों की सांस्कृतिक विभिन्नता, उनकी कला को हमें एक मंच पर देखने और जानने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी समुदाय की बेहतरी के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के नवनिर्माण में सबकी भागीदारी हो, सबका विकास हो, यह हमारी प्राथमिकता है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों और फैसलों से राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य हैं, जिसमें एक निजी उद्योग के लिए अधिग्रहित 4200 एकड़ जमीन आदिवासियों को वापस कराई है। वनवासियों को हम व्यक्तिगत और सामुदायिक पट्टे दे रहे हैं। गौठानों में दो रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है। गोबर विक्रेता ग्रामीणों एवं पशुपालकों को इसके एवज में 104 करोड़ रूपए करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। गौठानों में इंडस्ट्रियल पार्क, लघु उद्योग एवं कृषि आधारित उद्योग लगाने का काम जारी है। हमारी सरकार राज्य के तीज-त्यौहार, कला-संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का सफल आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य ने किया। कोरोना संक्रमण की वजह से बीते वर्ष इसका आयोजन नहीं हो सका। इस साल सभी लोगों के आग्रह पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव एवं राज्योत्सव का आयोजन एक साथ किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के मुख्यमंत्रियों ने ठोड़का और तुरही के साथ की जुगलबंदी

राजधानी रायपुर के साईंस कॉलेज मैदान पर चल रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान आदिवासी बाहुल्य राज्यों छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के मुख्यमंत्रियों ने भी पारंपरिक वाद्य ठोड़का और तुरही बजाकर जुगलबंदी की। झारखण्ड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब ठोड़का बजाना शुरू किया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरही बजाकर उनका साथ दिया। यह दिलचस्प नजारा जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल पर नजर आया। इस स्टॉल में जनजातीय समुदायों में प्रचलित पारंपरिक वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव-राज्योत्सव 2021 के मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आयोजन स्थल में छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों द्वारा लगायी गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ कर उसका अवलोकन किया। मुख्यमंत्री द्वय ने जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, आजीविका गुड़ी (आरांईपीए) के स्टालों का निरीक्षण कर उनके कार्य प्रणाली से अवगत हुए।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से आदिवासी संस्कृति को देश और विश्व पटल पर स्थापित करना है। उन्होंने महोत्सव में भाग लेने के लिए आए विदेशी कलाकारों सहित देश के सभी राज्यों के कलाकारों का छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से स्वागत किया। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का एकलौता राज्य है, जो इस तरह का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि यह आयोजन, सांस्कृतिक एवं भाषायी विविधता और पुरानी परंपरा को एक सूत्र में पिरोकर, अनेकता में एकता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान हम विभिन्न देशों एवं राज्यों से आए कलाकारों की कला का प्रदर्शन देखेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे और मेहमान कलाकार छत्तीसगढ़ से सुमधुर यादें अपने साथ लेकर जाएंगे।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिप्स के स्टॉल का भ्रमण किया

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव-2021 में साइंस कॉलेज मैदान में चिप्स स्टॉल का भी भ्रमण किया। चिप्स के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजितेश पांडेय ने चिप्स द्वारा स्टॉल में प्रदर्शित विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुख्यमंत्री को जानकारी प्रदान की। उल्लेखनीय है कि चिप्स द्वारा स्टाल में गोधन न्याय योजना की वेबसाइट और मोबाइल एप, क्वांटिफाइबल आयोग हेतु वेबसाइट और मोबाइल एप, भौगोलिक सूचना प्रणाली, 36कल्लू इनोवेशन सेंटर, विद्यार्थी जीवन चक्र प्रणाली, भरतनेट आदि योजनाओं की पोस्टर और ब्रोशर आदि के माध्यम से राज्योत्सव 2021 में आने वाले आम नागरिकों को सम्पूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा 36कल्लू इनोवेशन सेंटर के स्टार्ट अप उंमियों द्वारा विकसित ड्रोन का भी प्रदर्शन चिप्स स्टाल में किया जा रहा है।

आदिवासी नर्तक दलों की प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध हुए बघेल और सोरेन

साइंस कॉलेज मैदान में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मुख्य मंच की दर्शक दीर्घा में बैठ कर नर्तक दलों की मनमोहक प्रस्तुति का अवलोकन किया। उनकी आकर्षक प्रस्तुति से दोनों मुख्यमंत्री सहित दर्शक मंत्रमुग्ध हो उठे। इस दौरान नाइजीरिया, फिलिस्तीन, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नर्तक दलों ने प्रस्तुति दी। छत्तीसगढ़ के माड़िया जनजाति के दल ने गौर सिंग नृत्य पर प्रस्तुत किया। दोनों मुख्यमंत्री ने नर्तक दलों की कला की सराहना की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में विभिन्न नर्तक दलों की प्रस्तुतियां देख रहे थे, तब फिलिस्तीन के काउंसलर डॉ. अबू जजेरा और नर्तक दल के कलाकारों ने अपने देश के पाराम्परिक गमछे से उनका अभिनन्दन किया और इस आयोजन में उनके देश के दल को दिए गए आमंत्रण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

वन क्षेत्रों में जल संवर्धन के साथ बढ़ेगी हरियाली-वन मंत्री अकबर

कैम्पा मद से वर्ष 2021-22 में 392 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत

नरवा विकास योजनाः 38 लाख संरचनाओं का होगा निर्माण

> मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य के वन क्षेत्रों में भू-जल संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बड़े तादाद में जल स्त्रोतों, नदी-नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य लिया गया है। इसके लिए नरवा विकास योजना के तहत कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 में 392 करोड़ रूपाए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।

इसमें 1 हजार 962 नालों के 8.17 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में 37 लाख 99 हजार भू-जल संरक्षण संबंधी संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल द्वारा हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया है। इसके तहत प्रदेश के दो राष्ट्रीय उंान, दो टायगर रिजर्व, 1 सामाजिक वानिकी तथा 1 एलीफेंट रिजर्व सहित 30 वन मंडलों के नालों में भू-जल संवर्धन संबंधी संरचनाएं निर्मित की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण, निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (कैम्पा) मद से बनने वाली इन जल संग्रहण संरचनाओं

से वनांचल में रहने वाले लोगों और वन्य प्राणियों के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। साथ ही नाले में पानी का भराव रहने से आस-पास की भूमि में नमी बनी रहेगी। इससे खेती-किसानी में सुविधा के साथ-साथ आय के स्रोत और हरियाली में भी वृद्धि होगी।

इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख राकेश चतुर्वेदी ने बताया कि नरवा विकास योजना के तहत कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2021-22 के अंतर्गत गुरूघासीदास राष्ट्रीय उंान सरगुजा के 50 नालों में 96 हजार 850 तथा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उंान जगदलपुर के 7 नालों में 13 हजार 559 संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इसी तरह इन्द्रावती टायगर रिजर्व बीजापुर के 93 नालों में एक लाख 80 हजार 847 तथा अचानक मार्ग टायगर रिजर्व लोरमी के 52 नालों में एक लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण होगा। इसके अलावा एलीफेंट रिजर्व सरगुजा के 64 नालों में एक लाख 23 हजार 580 तथा अनुसंधान एवं विस्तार जगदलपुर के अंतर्गत 33 नालों में 63 हजार से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।

इसी तरह वन मंडलवार खैरागढ़ के 33 नालों में 64 हजार 775, बालोद के 20 नालों में 38 हजार 678, राजनांदगांव के 80 नालों में एक लाख 54 हजार 475 तथा कवर्धा के 75 नालों में एक लाख 35 हजार 275 संरचनाओं का निर्माण होगा। बिलासपुर के 50 नालों में 96 हजार 850, मरवाही के 128 नालों में 2 लाख 48 हजार 516, कोरबा के 83 नालों में एक लाख 59 हजार 802 तथा कटघोरा के 50 नालों में 96 हजार 850 संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। रायगढ़ के 19 नालों में 36 हजार 415, धरमजयगढ़ के 86 नालों में एक लाख 65 हजार 613, जांजगीर-चांपा के 5 नालों में 9 हजार 685 तथा मुंगेली के 35 नालों में 68 हजार 614 संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।

रायपुर के छह नालों में 12 हजार, बलौदाबाजार के 97 नालों में एक लाख 87 हजार 970, धमतरी के 10 नालों में 19 हजार 757, सुकमा के 65 नालों में एक लाख 24 हजार 936, बीजापुर के 28 नालों में 53 हजार 752 तथा दंतेवाड़ा के 5 नालों में 10 हजार 575 संरचनाओं का निर्माण होगा। जशपुर के 50 नालों में 96 हजार 850, सरगुजा के 49 नालों में 94 हजार 913, सूरजपुर के 35 नालों में 68 हजार 279, बलरामपुर के 136 नालों में 2 लाख 64 हजार 987 संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। कोरिया के 123 नालों में 2 लाख 37 हजार 669, मनेन्द्रगढ़ के 85 नालों में एक लाख 63 हजार 676, कांकेर के 74 नालों में एक लाख 43 हजार 904 तथा पूर्व भानुप्रतापपुर के 25 नालों में 48 हजार 426 संरचनाओं का निर्माण होगा। वन मंडलवार केशकाल के 33 नालों में 64 हजार 260, पश्चिम भानुप्रतापपुर के 43 नालों में 82 हजार 710, दक्षिण कोण्डागांव के 75 नालों में एक लाख 44 हजार 451 तथा नारायणपुर के 60 नालों में एक लाख 16 हजार 220 संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा।

राज्योत्सव-2021 अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा

उल्लेखनीय कार्य करने वालों को मिला अलंकरण पुरस्कार

राज्य उत्सव में विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले को अलंकरण पुरस्कार दिया गया। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने महंत घासीदास सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता में राज्योत्सव के अवसर पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा की।

अलंकरण पुरस्कारों में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार बिलासपुर जिले के ग्राम लिम्हा (नवापारा) के जानकी प्रसाद पुलस्त को दिया जाएगा। गृह पुलिस विभाग द्वारा अपराध अनुसंधान क्षेत्र में पंडित लखन लाल मिश्र सम्मान दुर्ग जिले के नेवई, थाना उतई के कुन्दनलाल गौर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाने वाले अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में यति यतनलाल सम्मान रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गुण्डाधूर सम्मान बिलासपुर जिले के खमतराई निवासी कुमारी रोहणी साहू, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महिला उत्थान के क्षेत्र में मिनीमाता सम्मान दुर्ग जिले के पंचशील नगर की डॉ. कल्पना देशमुख, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक चेतना और दलित उत्थान के क्षेत्र में गुरू घासीदास सम्मान दुर्ग जिले के आलबरस, थाना अण्डा के श्री पुरानिक लाल चेलक, सहकारिता विभाग द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक रायपुर को प्रदान किया जाएगा।

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा उर्दू की सेवा क्षेत्र में हाजी हसन अली सम्मान दुर्ग जिले के न्यू आदर्श नगर के जनाब रौनक जमाल, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान रायपुर जिले के सरोना की विद्या राजपूत, संस्कृति विभाग द्वारा साहित्य-आंचलिक के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंडित सुन्दरलाल शर्मा सम्मान बिलासपुर के नंदकिशोर तिवारी, संस्कृति विभाग द्वारा संगीत एवं कला के क्षेत्र में चक्रधर सम्मान संयुक्त रूप से दुर्ग जिले के भिलाई नगर निवासी प्रभंजय चतुर्वेदी और रायपुर के सुनील तिवारी को प्रदान किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा भी लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिए जाने वाला दाऊ मंदराजी सम्मान संयुक्त रूप से बिलासपुर जिले के रतनपुर निवासी काशीराम साहू और मुंगेली जिले के कुकुसदा निवासी रेखा देवार को प्रदान किया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा कृषि के क्षेत्र में डॉ. खूबचंद बघेल सम्मान रायगढ़ जिले के बरमकेला-नवापाली निवासी मुकेश चौधरी, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सामाजिक समरसता क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए महाराजा अग्रसेन सम्मान बस्तर जिले की के.एम.नायडू, समाज कल्याण विभाग द्वारा दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में दानवीर भामाशाह सम्मान मुंगेली जिले की भवानी साव रामलाल साव धमार्दा ट्रस्ट गांधीवार्ड, मत्स्य विभाग द्वारा मछली पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्रीमती बिलासाबाई केंवटीन मत्स्य विकास पुरस्कार दुर्ग जिले के मड़ियापार-धमधा के अनिल कुमार साहू को प्रदान किया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत भाषा के क्षेत्र में संस्कृत भाषा सम्मान रायपुर प्रोफेसर कॉलोनी भैया तालाब के पास निवास करने वाले डॉ. तोयनिधि वैष्णव, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासियों की सेवा और उत्थान के क्षेत्र में दिया जाने वाला भंवर सिंह पोर्ते सम्मान जंगो रायतार समाज कल्याण समिति छत्तीसगढ़ को प्रदान किया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा श्रम के क्षेत्र में महाराजा रामानुज प्रताप सिंहदेव सम्मान संयुक्त रूप से एनटीपीसी थर्मल पॉवर स्टेशन जमनीपाली कोरबा, प्रसेनजीत साहा, वी. जनार्दनराव, रामलाल और दीपक कुमार पंडित को प्रदान किया जाएगा। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बुनकर क्षेत्र में बिसाहूदास महंत पुरस्कार वर्ष 2018-19 जांजगीर-चांपा जिले के सुनील कुमार और राजाराम देवांगन तथा वर्ष 2019-20 का पुरस्कार जांजगीर-चांपा जिले के ही श्री तुकाराम देवांगन और श्रीराम देवांगन को प्रदाय किया जाएगा। ग्रामोद्योग विभाग द्वारा बुनकर के क्षेत्र में राजराजेश्वरी करूणामाता हाथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार बलौदाबाजार भाटापारा के विकासखंड बिलाईगढ़ के राजेश कुमार देवांगन और बिलाईगढ़ विकासखंड के ग्राम पेण्ड्रावन निवासी टीकाराम देवांगन को दिया जाएगा।

संस्कृति विभाग द्वारा प्रदर्शनकारी लोककला क्षेत्र में देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ निवासी हृदय प्रकाश अनंत और वर्ष 2021 के लिए दुर्ग जिले के छोटैरी भिलाई-3, छोटैरी निवासी अमोलदास टंडन, संस्कृति विभाग द्वारा लोक शैली पंथी नृत्य प्रदर्शनकारी कला क्षेत्र में देवदास स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार दुर्ग जिले के पेण्ड्रतराई निवासी श्री गौकरण दास बघेल, संस्कृति विभाग द्वारा हिन्दी-छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा, निर्माण के क्षेत्र में किशोर साहू सम्मान रायपुर के मनमोहन सिंह ठाकुर, संस्कृति विभाग द्वारा ही हिन्दी-छत्तीसगढ़ी सिनेमा में निर्देशन के लिए दिया जाने वाला किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण मुम्बई के अपूर्व बड़गैय्या को प्रदान किया जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा तथा शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए धनवंन्तरि सम्मान रायपुर फाफाडीह निवासी डॉ. के.बी. श्रीनिवास राव को प्रदान किया जाएगा। जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया (हिन्दी) के क्षेत्र में चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार दंतेवाड़ा की अम्बु शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हिन्दी के क्षेत्र में अंशुमान शर्मा, जनसपर्क विभाग द्वारा प्रिंट मीडिया अंग्रेजी के क्षेत्र में मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार रायपुर पुरानी बस्ती निवासी टिकेश्वर पटेल, जनसंपर्क विभाग द्वारा ही रचनात्मक लेखन और हिन्दी भाषा क्षेत्र में प्रदाय किए जाने वाले पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मकता सम्मान नई दिल्ली निवासी मृणाल पाण्डे को प्रदान किया जाएगा। विधि एवं विधायी विभाग द्वारा विधि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान बलौदाबाजार निवासी ठाकुर भूपेन्द्र प्रताप सिंह और रायपुर निवासी कुमारी शमीम रहमान को प्रदान किया जाएगा।

बेरोजगारों को मिली नई पहचान

बदलता दन्तेवाड़ाः नवचेतना बेकरी से बदली जिन्दगी

दंतेवाड़ा जिले में लोगों को रोजगार दिलाने की एक नई पहल शुरू हुई है। जहां नवचेतना बेकरी का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 31 जनवरी 2021 में की गई थी। इसमें मुख्य रूप से मानव तस्करी, ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांग वर्ग के 6 लोगों को रोजगार दिया गया है। इनके द्वारा इस बेकरी में केक, कुक्कीस, पेस्ट्री इत्यादि बनाई जाती है। बेकरी से न सिर्फ उन्हें रोजगार मिला है बल्कि उनके जीवन मे भी सकारात्मक सुधार आया है, और सम्मानपूर्वक अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। काम देने के पूर्व उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है, जिससे बेहतर तरीके से वे कार्य कर रहे हैं। बेकरी में तैयार किये गए उत्पाद ब्रेड, बिस्किट और केक स्थानीय उपज से उत्पाद तैयार किया जाता है। जो कि बाकी जगहों से मिलने वाले उत्पाद के मुकाबले स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब तक नवचेतना बेकरी द्वारा 3 लाख 50 हजार 981 रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित हुआ है। दंतेवाड़ा जिले में बेरोजगारों को रोजगार देने और स्थानीय उपज को बाजार में बिक्री कराने प्रशासन की पहल निश्चित ही गरीबी उन्मूलन की दिशा में लाभदायक सिद्ध होगा। ट्रांसजेंडर, दिव्यांग लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है मुख्य रूप से ट्रांसजेंडर जिनका जीवन अत्यंत मुश्किल भरा होता है। पैसे कमाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अपनी पहचान को स्वीकारने के लिए संघर्ष करना पड़ा था। परन्तु अब समाज और शासन के समर्थन और मदद से उनके जीवन मे बदलाव आया है। दिव्यांगों, ट्रांसजेंडर को रोजगार के अवसर प्रदान किया गया है। एक बेहतर राष्ट्र व समाज के लिए विभिन्न वर्गों में समानता अनिवार्य है। अब इन्हें भी रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस पहल की शुरूआत होने से दिव्यांग युवाओं को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराया गया है। हर वर्ग के लोगों को यहां पर रोजगार प्रदान किया गया हैं। साथ ही सभी के लिए एक समान अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। बेकरी में कार्य कर वे संतुष्ट है। अब उनके काम को सराहा जा रहा है साथ ही उनका आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है और लगातार बेहतर कार्य करने की कोशिश की जा रही है। सभी मेहनत, लगन और मन लगाकर अपना काम कर रहे हैं।

मुर्गी पालन कर महिलाएं हो रही स्वावलंबी

स्वयं के रोजगार से अर्जित कर रही अच्छी आय

गांवों में पशुपालन के साथ ही मुर्गी पालन को हमेशा से वैकल्पिक पालन के तौर ही किया जाता रहा है। जिसे कभी भी व्यावसायिक दृष्टि से नही देखा गया था। लेकिन राज्य शासन की आजीविका संवर्धन योजनाओं और सहयोग से यह बदलाव गांवो में दिखाई दे रहा है। राज्य शासन की ग्राम सुराजी योजना अंतर्गत रायगढ़ ब्लाक के ग्राम पंचायत डोंगीतराई में मुर्गी शेड का निर्माण कर मुर्गी पालन और ब्रिकी कर समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। समूह की महिलाएं इस रोजगार के माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर पा रही है।

शासन द्वारा मुर्गी शेड की स्वीकृति महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ग्राम पंचायत डोगीतराई में मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण का प्रस्ताव के पश्चात एक माह में ही प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई। मुर्गी शेड निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा से 2 लाख 15 हजार, मजदूरी मद से 17 हजार 800 तथा सामग्री मद से 01 लाख 83 हजार 700 रुपये इस तरह कुल 4 लाख 3 हजार की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रशासकीय स्वीकृति के पश्चात जनपद पंचायत रायगढ़ द्वारा कार्यादेश तथा शेड निर्माण हेतु स्थल चिन्हांकित कर तीन माह में ही शेड निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया। मुर्गी शेड निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात आजीविका संवर्धन हेतु 7 सदस्यों की गायत्री स्व-सहायता समूह को हस्तांतरित कर दिया गया। जिसके पश्चात महिला समूह को पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विभाग रायगढ़ द्वारा 430 मुर्गी चूजा प्रदान किया गया। समूह की महिलाओं के संगठित प्रयास और मेहनत के फलस्वरूप आज महिला समूह द्वारा तीस किलोग्राम मुर्गी विक्रय कर 09 हजार तक की राशि प्राप्त की जा चुकी है। मुर्गी पालन से हो रहे अच्छे लाभ को देखते हुए समूह की महिलाओं में मुर्गी पालन को लेकर काफी उत्साह है। समूह की अध्यक्ष पार्वती वैष्णव का कहना है कि मुर्गी शेड के निर्माण होने तथा पशुपालन विभाग द्वारा निःशुल्क चूजा मिलने के पश्चात समूह की महिलाओं की ही मेहनत है कि आज मुर्गी विक्रय प्रारंभ किया जा चुका है और अच्छा लाभ मिल रहा है। इसके अलावा आय में वृद्धि के लिए समूह कि महिलाएं अन्य गतिविधियां भी संचालित कर रही है। समूह की महिलाओं ने सुराजी गांव योजना के तहत गोठान स्थल में महिलाओं के आजीविका संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए शासन एवं जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया।

25 हजार करोड़ के 325 प्रोजेक्ट्स से राम नगरी बनेगी हेरिटेज और स्मार्ट

> असल मायने में यह अयोध्या के लोगों को राज्य सरकार का असली दिवाली गिफ्ट है। अयोध्या के साल 2047 के इस विजन डॉक्यूमेंट में 25 साल बाद की राम नगरी का खाका खींचा गया है।

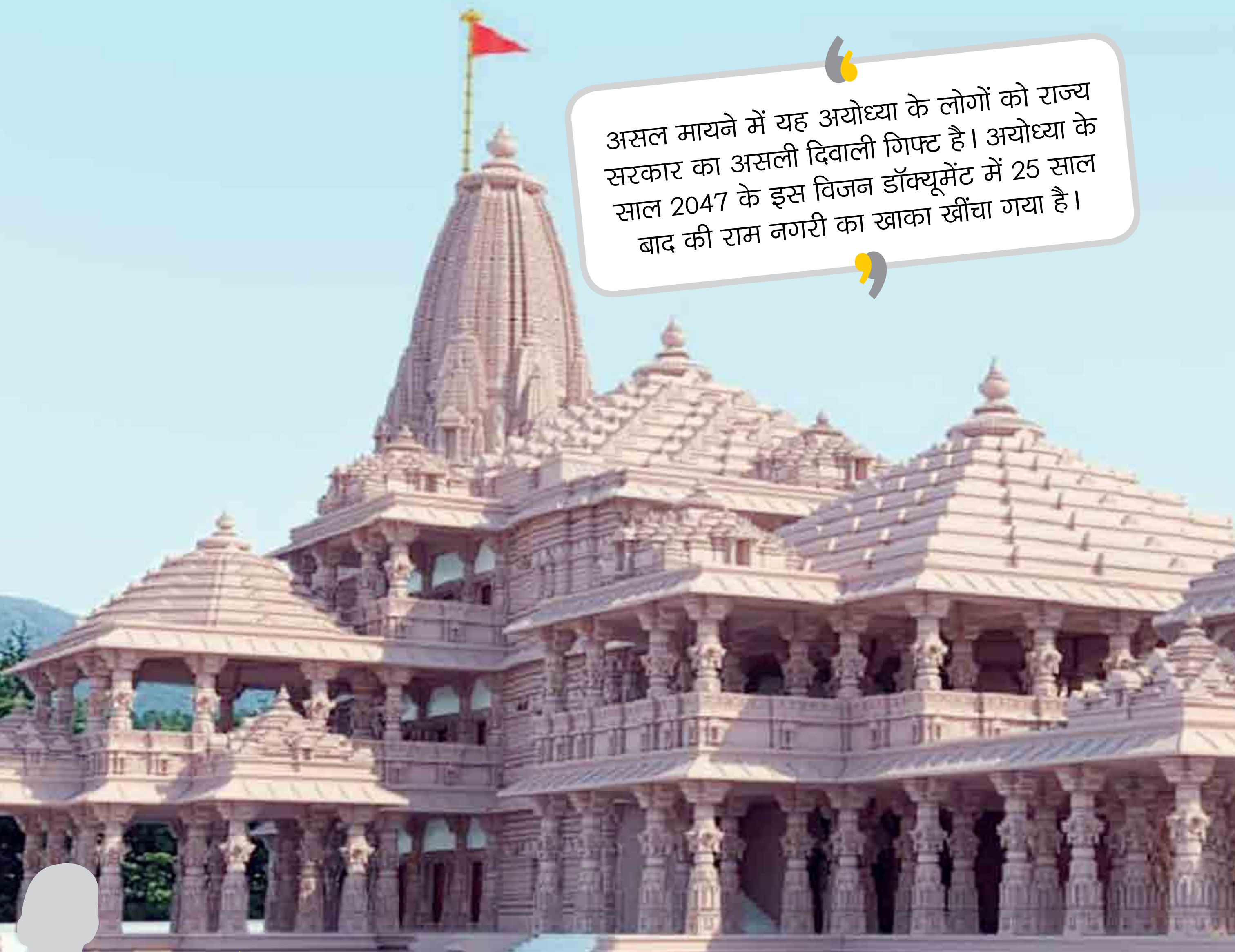

अयोध्या के विकास के इस ब्लूप्रिंट में 25 हजार करोड़ रुपये के 325 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जो राम नगरी को हेरिटेज और वर्ल्ड क्लास स्मार्ट लुक देंगे। इन प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन साल 2047 रखी गई है यानी आजादी के 100 साल पूरे होने पर। इस प्रोजेक्ट में अयोध्या को देश का सबसे दिव्य और भव्य शहर बनाने का विजन है। 3 नवंबर को अयोध्या में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दीपोत्सव मनाएंगे, उससे पहले उनके सामने ये विजन डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। प्रोजेक्ट्स पूरे करने को लेकर अंतिम मुहर लगेगी। इन प्रोजेक्ट्स को स्क्रीन पर देश भर से आए 10 हजार अतिथियों को भी दिखाया जाएगा।

पीएम मोदी ने के खारिज करने पर बदला गया

इसी साल 26 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट का प्रजेंटेशन देखा था। लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया था। उन्होंने इसे नए सिरे से बनाने को लेकर निर्देश और सुझाव दिए थे। अब पीएम के सुझाव के हिसाब से इसमें बदलाव किए गए हैं। दीपोत्सव समारोह के दौरान ही यूपी सरकार 30 मिनट का विजन डॉक्यूमेंट पेश करेगी। इससे जनता को अयोध्या के विकास लेकर सरकार की कोशिश का पता चलेगा।

तिरुपति से लेकर वेटिकन सिटी तक के प्रोजेक्ट खंगाले

अयोध्या का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए प्रयागराज, काशी, मथुरा, उज्जैन, तिरूपति, सोमनाथ मंदिर का अध्ययन किया गया। इसके साथ ही कंबोडिया से लेकर वेटिकन सिटी तक के विकास मॉडल, विकास व बेंचमार्क के भी पन्ने पलटे गए हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विशाल सिंह के मुताबिक, अयोध्या को मिनी भारत के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। शहर के विकास में आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता के समावेश पर फोकस होगा।

तीर्थ, हैरिटेज और स्मार्ट सिटी का कॉम्बिनेशन वाला होगा नया शहर

- वैदिक नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। रामायण युग के और पौराणिक महत्व वाले जलाशयों, कुंडों, झीलों को संरक्षित किया जाएगा।
- समरस शहर बनाने के लिए वाल्मीकि रामायण युग की 88 प्रजातियों के 27000 पेड़ भी लगाए जाएंगे।
- स्मार्ट सिटी के तहत इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, मल्टीलेवल कार पार्किंग, बाहरी रिंग रोड और ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया जाएगा।।

7 प्वाइंट में जानिए अयोध्या का विजन-2047 क्या है?

- विदेशी पर्यटकों से लिया फीडबैकः विजन डॉक्यूमेंट पांच हजार लोगों और 500 दुनिया भर के पर्यटकों के सुझाव के आधार पर तैयार किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट पूरे होने से 4 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार और 8 लाख से ज्यादा को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा।
- मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डाः इसके लिए 79 प्रतिशत भूमि मिल चुकी है।
- ग्रीन फील्ड टाउनशिप का प्लानः अयोध्या के अन्दर 12 सौ एकड़ भूमि में नव्य अयोध्या के तहत ग्रीन फील्ड टाउनशिप तैयार की जाएगी। इसमें मठ, आश्रम, राज्य के गेस्ट हाउस, अंतरराष्ट्रीय भवन, हॉस्पिटल, स्कूल, होटल, आवासीय प्लॉट होंगे।
- भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगेः अयोध्या में चार मुख्य राम द्वार का निर्माण किया जाएगा। गेट का डिजाइन राम मंदिर के डिजाइन से प्रेरित होगा।
- पर्यटन सुविधा केंद्रः अयोध्या के हाईवे रूट पर बने 6 प्रवेश द्वारों पर धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। लखनऊ मार्ग पर 600 कमरे, रायबरेली मार्ग पर 200 कमरे, प्रयागराज मार्ग पर 200 कमरे, आजमगढ़ मार्ग पर 250 कमरे, गोंडा मार्ग पर 370 कमरे, गोरखपुर मार्ग पर 210 कमरे होंगे।
- अंतरराष्ट्रीय संग्रहालयः उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग 200 करोड़ की लागत से पर्यटन सुविधा केंद्र और अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण करेंगे।
- रिवर फ्रंट डेवलपमेंटः सरयू तट डेवलपमेंट की भी योजना है, जिसमें 2300 एकड़ में रामायण स्प्रिचुअल फॉरेस्ट तैयार किया जाएगा। इसमें रामायण स्प्रिरिचुअल थीम पार्क भी होगा।

मत्स्य कृषकों अब बिना ब्याज सहकारी समितियों से मिलेगा ऋण

मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिलने से पानी और बिजली में भी छूट का लाभ

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा देने से मछुवारों एवं मत्स्य कृषकों को अपने मत्स्य कारोबार के लिए किसानों के समान सहकारी समितियों से शून्य प्रतिशत ब्याज पर न सिर्फ ऋण मिल सकेगा, बल्कि मत्स्य पालन के लिए सिंचाई जलाशयों से बिना किसी शुल्क के पानी और बिजली की भी सुविधा मिलेगी। इससे मत्स्य पालन को राज्य में बढ़ावा मिलने के साथ मत्स्य उत्पादन की लागत में कमी आएगी। जिसका सीधा लाभ मछुवारा एवं मत्स्य कृषकों को होगा। छत्तीसगढ़ शासन के इस निर्णय से धमतरी जिले के लगभग 8 हजार मत्स्य पालक लाभान्वित होंगे। धमतरी जिले तालाब और जलाशयों में मछली पालन किया जा रहा है, जो कि हजारों लोगों की आजीविका का साधन है। जिले के 3561 ग्रामीण तालाब, जिसका जलक्षेत्र 4322.172 हेक्टेयर है। इसमें से 3334 ग्रामीण तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है। इसी तरह जिले में 50 सिंचाई जलाशयों में मछली पालन किया जा रहा है। मछली बीज उत्पादन एवं संचयन के लिए जिले में छः हैचरी हैं। इनमें सांकरा स्थित शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र सह हेचरी में दो हैचरी, छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ के अधीन देमार में दो हैचरी, परखंदा में एक हैचरी और एक निजी हैचरी कुसुमखुंटा में है। इसी तरह जिले में पांच मत्स्य बीज प्रक्षेत्र स्थापित है। इनमें सांकरा स्थित शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्र सह हैचरी, देमार और परखंदा में छत्तीसगढ़ मत्स्य महासंघ के अधीन एक-एक प्रक्षेत्र तथा कुसुमखुंटा और सिहावा में निजी प्रक्षेत्र शामिल है। ज्ञात हो कि शासकीय मत्स्य बीज प्रक्षेत्रों से मत्स्य पालकों को रियायती शासकीय दर पर मत्स्य बीज उपलब्ध कराई जाती है।

रियायत से लक्ष्य से ज्यादा संग्रहित हुआ राजस्व

पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण

वर्ष 2020-21 में 5.90 प्रतिशत अधिक हुआ संग्रह

राज्य शासन द्वारा दस्तावेजों के बाजार मूल्य निर्धारण करने वाली गाईडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की कमी 25 जुलाई 2019 से की गई। विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा उक्त 30 प्रतिशत की कमी को वर्ष 2020-21 एवं वर्ष 2021-22 के लिए भी यथावत रखा गया है। सम्पत्ति के बाजार मूल्य में कमी के साथ ही सम्पत्ति के खरीदी बिक्री में राहत प्राप्त होने से समाज के सभी वर्ग के लिए भूमि, मकान खरीदना आसान हुआ है। इसी तरह से आवासीय भवनों के पंजीयन में 2 प्रतिशत की रियायत दी गई है। शासन द्वारा 75 लाख रूपए कीमत तक के मकान व भवन के विक्रय संबंधी विलेखों पर प्राभार्य होने वाले पंजीयन शुल्क की दर में दो प्रतिशत की रियायत अगस्त 2019 से प्रदान की गई है, जिसे नागरिकों के हितों में ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के लिए पंजीयन शुल्क की रियायत को यथावत रखा गया है।

भूमि खरीदी बिक्री के लिए दी गई रियायतों से छोटे एवं मध्यम परिवारों को अपने मकान खरीदने का सपना पूरा हो रहा है। राज्य शासन द्वारा भूमि के क्रय-विक्रय और मकानों और फ्लेट में दी जा रही पंजीयन में छूट से मकान और भूमि खरीदी के लिए कम कीमत देनी होगी।

"चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वित्त विभाग की ओर से निर्धारित राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 1650 करोड़ रूपए है। अब तक 714.57 करोड़ रूपए राजस्व प्राप्त हुआ है, जो की गत वर्ष की इसी अवधि की राजस्व प्राप्ति 496.58 करोड़ रूपए की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनवरी 2019 में आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए छोटे भू-खण्डों के विक्रय पर लगी रोक को हटाकर ई-पंजीयन प्रणाली में आवश्यक प्रावधान कराया गया। जनवरी 2019 से अब तक छोटे भू-खण्डों से संबंधित 3 लाख से ज्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ है।"

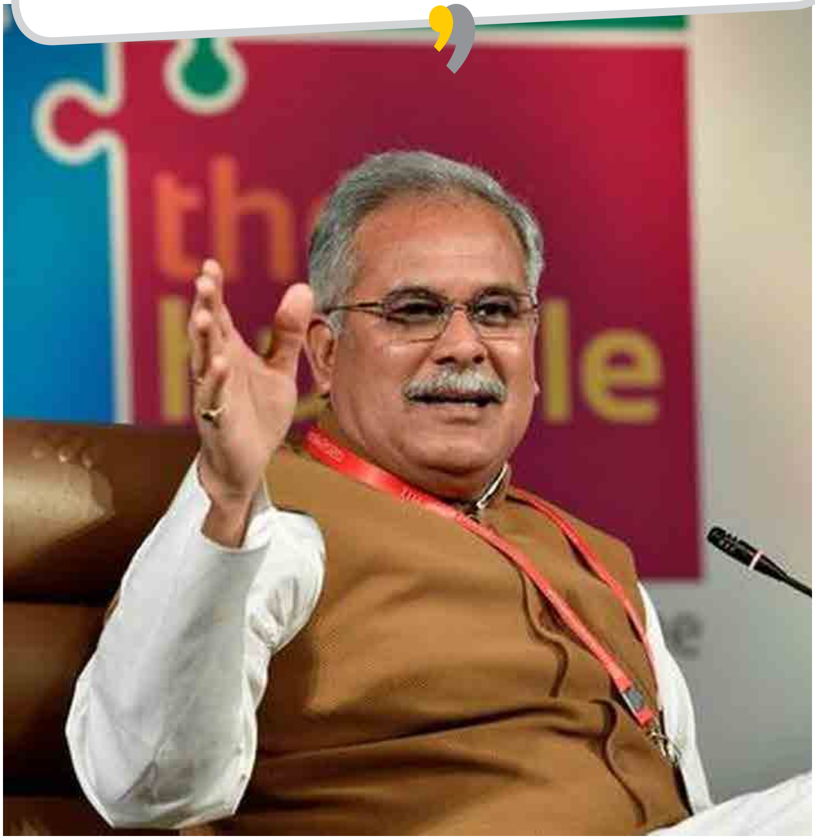

हर राज्य में एम्स और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेगा : पीएम मोदी

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड से स्थापित 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर उसे राष्ट्र को समर्पित किया। अब तक पूरे देश में कुल 1224 ऑक्सीजन संयंत्रों को पीएम केयर्स फंड से इकट्ठा हुई राशि के द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड के तहत 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर उसे राष्ट्र को समर्पित किया।

इनमें से 1100 ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो चुकी है, जिसके माध्यम से देश के विभिन्न अस्पतालों में 1750 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन प्रतिदिन मिलेगी। उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में आयोजित ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने जनता को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने ना सिर्फ कोरोना काल के दौरान सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की बल्कि उन्होंने भारत में चल रहे कोरोना टीकाकरण अभियान को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान बताया। इस मौके पर पीएम मोदी ने हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कई बातें कही जिनके बारे में हम आपको यहां बता रहे हैं:

हर राज्य में एम्स और हर जिले में मेडिकल कॉलेज

पीएम मोदी ने कहा 6-7 साल पहले तक सिर्फ कुछ राज्यों तक ही एम्स की सुविधा थी, आज हर राज्य तक एम्स पहुंचाने के लिए काम हो रहा है। 6 एम्स से आगे बढ़कर 22 एम्स का सशक्त नेटवर्क बनाने की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का ये भी लक्ष्य है कि देश के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो।'

पहले के मुकाबले 10 गुणा बढ़ा मेडिकल ऑक्सीजन

पीएम मोदी ने अपने सम्बोधन में कहा, 'सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मीट्रिक टन, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रॉडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रॉडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया। ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया।'

1 टेस्टिंग लैब से करीब 3 हजार टेस्टिंग लैब्स का नेटव

पीएम मोदी ने कहा, 'कोरोना से लड़ाई के लिए इतने कम समय में भारत ने जो सुविधाएं तैयार कीं, वो हमारे देश के सामर्थ्य को दिखाता है। सिर्फ 1 टेस्टिंग लैब से करीब 3 हजार टेस्टिंग लैब्स का नेटवर्क, मास्क और किट्स के आयातक से निर्यातक बनने का सफर तय किया है।'

भारत ने वैक्सीनेशन के लिए दुनिया को राह दिखाई

पीएम मोदी ने कहा, 'ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएंगे। भारत ने कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन किया कैसे जाता है।' पीएम ने कहा, 'देश के दूर-दराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं, मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन का तेजी से और बड़ी मात्रा में निर्माण, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज टीकाकरण अभियान भारत ने जो कर दिखाया है, वो हमारी संकल्पशक्ति, हमारे सेवाभाव, हमारी एकजुटता का प्रतीक है।'

CVRU

विद्या परं देवतम्

DR. C.V.RAMAN UNIVERSITY

दीप पर्व पर
जगमगाती लाखों दीपमालिकाओं
की उज्ज्वल रोशनी,
आपको एवं आपके परिजनों को सुख-शांति व
समृद्धि से परिपूर्ण रखें

दीपावली की शुभकामनाएं...

15 Years of Moulding Careers

The National Assessment and Accreditation Council GRADE B+ NAAC

DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur AN AISECT GROUP UNIVERSITY

Approved by : AICTE | NCTE | BCI | PCI | AIU | Joint Committee : (UGC | DEB | AICTE) | Recognized by : UGC | A NAAC Accredited University

Kargi Road, Kota, Bilaspur (C.G.), Phone: 07753-253801
Email: admissions@cvru.ac.in, info@cvru.ac.in

AdPRAYAS

2-18 साल तक के बच्चों को अब जल्द लगेगा टीका

भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मिली मंजूरी

देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खुशखबरी है। बच्चों के लिए वैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की कमिटी ने बच्चों के लिए बनी भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को अपनी मंजूरी दे दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत बायोटे क की कोवैक्सीन अब देश में 2 से 18 साल तक के बच्चों को दी जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर जल्द गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। बता दें कि भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। देश में भारत बायोटेक ऐसी पहली ऐसी कंपनी है जिसने बच्चों के लिए वैक्सीन पर ट्रायल किया था। सेकेंड फेज-थर्ड फेज के ट्रायल के बाद जिसके बाद कंपनी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय की कमिटी को सौंपी थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। अब इसके साथ ही बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जाएगी। बताया गया है कि बच्चों को भी बड़ों की तरह कोवैक्सीन की दो टीके लगेंगे। सूत्रों के मुताबिक, उन बच्चों को पहले वैक्सीन लगाई जा सकती है जिनको अस्थमा आदि की दिक्कत है। सरकारी जगहों पर यह वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। एक सप्ताह पहले भारत बायोटेक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल के लिए कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन के दूसरे चरण का परीक्षण पूरा कर लिया था और इसके सत्यापन तथा आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए आंकड़े केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) को सौंप दिए थे। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने सितंबर में बताया था कि बच्चों को लगने वाले वैक्सीन ट्रायल पूरा कर लिया गया है और आंकड़ों का विश्लेषण कर जल्द ही मंजूरी के लिए मंत्रालय को भेज दिया जाएगा। इस दौरान कंपनी ने कहा था कि अक्टूबर में कोवैक्सीन का उत्पादन 5.5 करोड़ खुराकों तक पहुंच जाएगा, जो सितंबर में 3.5 करोड़ है।

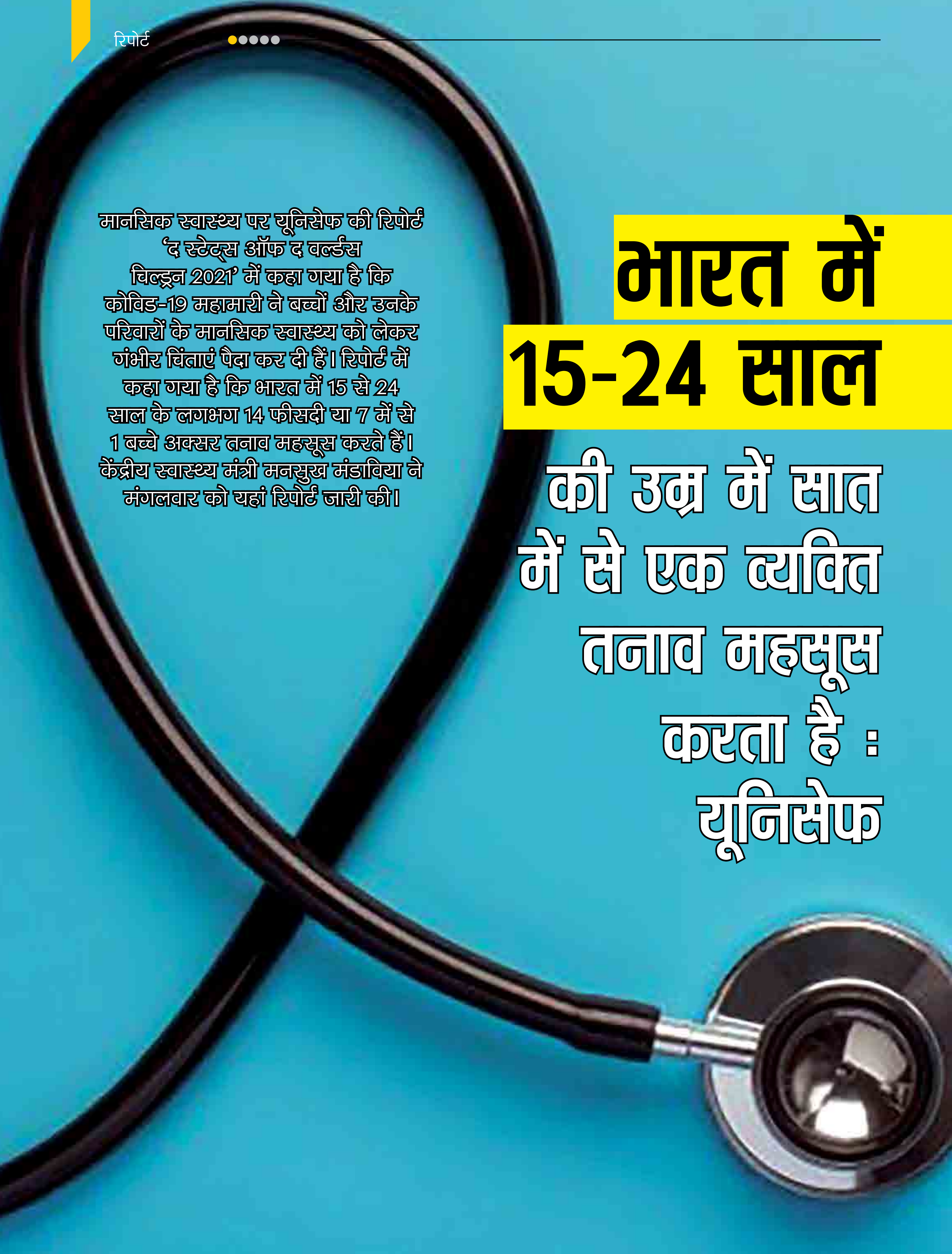

भारत में 15-24 साल की उम्र में सात में से एक व्यक्ति तनाव महसूस करता है : यूनिसेफ

मानसिक स्वास्थ्य पर यूनिसेफ की रिपोर्ट 'द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021' में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी ने बच्चों और उनके परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 15 से 24 साल के लगभग 14 फीसदी या 7 में से 1 बच्चे अक्सर तनाव महसूस करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को यहां रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट ने साफ किया है कि दुनिया में होने वाली घटनाएं हमारे दिमाग के अंदर की दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। 21 देशों में यूनिसेफ के सर्वेक्षण में, भारत में केवल 41 प्रतिशत युवा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए समर्थन लेने के इच्छुक थे, जबकि 21 देशों के लिए यह औसत 83 प्रतिशत था।

रिपोर्ट जारी करते हुए मंत्री मंडाविया ने कहा, 'हमारी सनातन संस्कृति और आध्यात्मिकता में मानसिक स्वास्थ्य की व्यापक रूप से चर्चा की गई है। हमारे ग्रंथों में मन और शरीर के पारस्परिक विकास की व्याख्या की गई है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। हमें बहुत खुशी है कि आज यूनिसेफ ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की है।'

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जैसे-जैसे हमारे समाज में संयुक्त परिवार की बजाय एकल परिवार का चलन बढ़ा है, बच्चों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं अक्सर हो गई हैं। आज माता-पिता अपने बच्चे को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमें मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करने की जरूरत है। हमें बताया गया है कि दुनिया भर में लगभग 14 प्रतिशत बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य समस्या है। यह गंभीरता से लेना होगा।'

साथ ही मंडाविया ने कहा, 'बेहतर और विकसित समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि समय-समय पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी की जाए। इसके लिए स्कूलों में शिक्षकों के बेहतर मानसिक स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि, बच्चे अपने शिक्षकों पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं।' अपने अनुभव को साझा करते हुए मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्हें दूसरी लहर के दौरान मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा।

उन्होंने कहा, 'लोगों की समस्याओं ने मुझे झकझोर दिया। उसके बाद मैंने सुबह योग और साइकिल चलाना शुरू किया। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपने मन की समस्याओं की जांच करें और उसकी बेहतरी के लिए काम करें। अपने बच्चों के साथ घर पर पर्याप्त समय बिताएं। उनसे दोस्ताना माहौल में बात करें।'

यूनिसेफ और गैलप द्वारा 2021 की शुरूआत में 21 देशों में 20,000 बच्चों और वयस्कों के साथ किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में बच्चे मानसिक तनाव के लिए समर्थन लेने में हिचकिचाते हैं। भारत में 15-24 वर्ष की आयु के बीच केवल 41 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सहायता प्राप्त करना अच्छा है, जबकि 21 देशों के लिए यह औसत 83 प्रतिशत है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन 21 देशों में से एक था, जहां केवल अल्पसंख्यक युवाओं को लगता था कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना करने वाले लोगों को दूसरों तक पहुंचना चाहिए। हर दूसरे देश में, अधिकांश युवाओं (56 से 95 प्रतिशत तक) ने महसूस किया कि मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है।

सर्वेक्षण के निष्कर्ष, जिनका पूर्वावलोकन द स्टेट ऑफ द वर्ल्डस चिल्ड्रन 2021 में किया गया है, उन्होंने यह भी पाया कि भारत में 15 से 24 वर्ष के लगभग 14 प्रतिशत या 7 में से 1 ने अक्सर तनाव महसूस किया या चीजों को करने में बहुत कम रुचि दिखाई। यह अनुपात कैमरून में लगभग तीन में से एक, भारत और बांग्लादेश में सात में से एक से लेकर इथियोपिया और जापान में दस में से एक के बराबर था। 21 देशों में, औसत पांच युवाओं में से एक था। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड -19 महामारी अपने तीसरे वर्ष में है। बच्चों और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव भारी पड़ रहा है। महामारी के माध्यम से, बच्चों को लॉकडाउन उपायों के कारण सामाजिक सेवाओं से समर्थन तक सीमित पहुंच प्राप्त हुई है। दिनचर्या, शिक्षा, मनोरंजन के साथ-साथ पारिवारिक आय और स्वास्थ्य के लिए चिंता के कारण कई युवा डर, क्रोधित और अपने भविष्य के लिए चिंतित महसूस कर रहे हैं।

यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार, 2020-2021 के बीच भारत में कक्षा 6 तक के 28.6 करोड़ से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर थे। 2021 में यूनिसेफ के तेजी से मूल्यांकन में पाया गया कि केवल 60 प्रतिशत ही डिजिटल कक्षाओं तक पहुंच सकते हैं। बहुत से लोग अपनी शिक्षा जारी नहीं रख पाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड -19 संकट से पहले भी, बच्चों और युवाओं ने उन्हें संबोधित करने में महत्वपूर्ण निवेश के बिना मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का सामना किया।

नई उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, 10-19 आयु वर्ग के 7 में से 1 से अधिक किशोरों के विश्व स्तर पर निदान मानसिक विकार के साथ रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के अनुसार, इनमें से दक्षिण एशिया में मानसिक विकारों वाले किशोरों की संख्या सबसे अधिक थी।

भारत में, मानसिक स्वास्थ्य विकारों वाले बच्चे ज्यादातर निदान नहीं करते हैं और मदद या उपचार लेने में झिझकते हैं। 2019 में इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के अनुसार, महामारी से पहले भी, भारत में कम से कम 5 करोड़ बच्चे मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से प्रभावित थे। 80 - 90 प्रतिशत ने समर्थन नहीं मांगा है। इस बीच, भारत में मानसिक स्वास्थ्य जरूरतों और मानसिक स्वास्थ्य फंडिंग के बीच व्यापक अंतर बना हुआ है।

नेता जी की खैरियत

क्या है कि नेताजी का बड़प्पन जो है महंगा पड़ गया। क्या है कि नेता दिल्ली उड़े तो बंगले में भी छुटभैया नेताओं की भीड़ लग गई। नेता जी को पता भी नहीं था और वापस लौटे तो एक खबर सुनकर चैंक गए। वो था पोस्टिंग लिस्ट। मनमर्जी ऐसी चली कि हाउस तक शिकायत पहुंच गई।

काम की बात

वो तो मंत्रालय यानि प्रवेश भी निषेध होता है। पर मंत्रालय में प्रवेश मिला तो बड़े-बड़े के भी होश उड़ जाते हैं। एक बार की बात है कि एक बड़े साहब तक एक बाहरी पहुंचा। पर पास कैसे बने, इसकी हकीकत का पता ही नहीं था, जब पता चला तो साहब के भी होश उड़ गए।

नाम का विभाग

घूमने-फिरने वाले विभाग में क्या है कि आज फंड का रोना बहुत है। सब काम फंड में ही होते है। पर क्या है कि फंड साहब की वजह से नहीं मिल रहा है। एक साहब ने आपत्ति ऐसी लगाई कि अब तक फंड का कोई भी पता नहीं चल पाया।

थिएटर की नौटंकी

राजधानी के एक बड़े सुपर स्पेशिलटी डीके अस्पताल में लंबे इंतजार के बाद लाखों रूपए की लागत से बनाया गया थियेटर खुल गया है। पुराने साहब ने उसमें कुछ फिल्म दिखाने का प्लान बनाया था। वो नोटंकी तो नहीं हो पाई पर मुददत के बाद उसका गेट खुला। पिछले दिनों इस थियेटर का ताला खोला गया और वहां बड़ा आयोजन भी किया। क्रिटिकल केयर आयोजित यह कार्यक्रम भी इतना क्रिटिकल था कि लोग इससे दूर रहे। खैर इस अस्पताल के निर्माण से जुड़े पुराने लोगों ने इस बात की राहत भरी सांस तो ली कि देर से सही अस्पताल का थियेटर खुला।

बेरोजगारी की बांसुरी

सरकारी नौकरी के लिए बेरोजगारों को बड़ी को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। देश में करोड़ों बेरोजगारों के बीच हर कड़ी में सफल होने के बाद नौकरी हाथ लगती है। फिर भी बेरोजगारी का आलम रहता है। सरकार तो अपनी तरफ से कहती है कि हमने सब हाथों को काम दिया है, इसके बाद भी बेरोजगारी कम नहीं होती। इससे मुक्ति पाने केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी कर पूरे देख में इसके सर्वे पर ही रोक लगा दी है। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी।

सबले बढ़िया

छत्तीसगढ़ को यूं ही सबले बढ़िया नहीं कह जाता है। यहां की तासीर ही सदभावना की है। सब चल जाता है। अब शिक्षा विभाग को ही लीजिए। जब छत्तीसगढ़ बना तब बहुत से कर्मचारी यहां मध्यप्रदेश से आए। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में आमद हुई। खबरी बता रहा था कि सैकड़ों ऐसे भी आए जिनका कोई रिकॉर्ड मध्यप्रदेश में नहीं था। अब तक यह कोई अता-पता नहीं किवे ककहां से आए, किसने भेजा और यहां कैसे नौकरी करते रहे।

13 वर्षीय एक बालिका को जब अस्पताल लाया गया तो उसकी स्थिति गंभीर थी। उसे पेट दर्द, सांस की तकलीफ, भ्रम, मितली जैसी शिकायतें थीं। पूछने पर उसने स्वीकार किया कि बार-बार प्यास लगती थी और फिर बार-बार पेशाब भी जाना पड़ता था। शंका होने पर बालिका के रक्त शर्करा की जांच की गई। उसे डायबिटीज था। ये लक्षण डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के लक्षणों से मेल खाते थे।

डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकती है जानलेवा

डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डीकेए एक जानलेवा दुर्लभ स्थिति है जो आमतौर पर टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में हो सकती है। इसका कारण आमतौर पर यही होता है कि रोगी को अपने डायबिटिक होने का पता ही नहीं होता। टाइप 1 डायबिटीज चूंकि जन्मजात होता है इसलिए इसके लक्षण बहुत कम उम्र के रोगियों में उभर सकते हैं। इसका प्रमुख कारण शरीर में इंसुलिन की कमी होती है। संक्रमण, कड़ी औषधियां और सर्जरी का तनाव इस स्थिति को ट्रिगर कर सकती है।

सभी कोशिकाओं को ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है। इंसुलिन की कमी के कारण कोशिकाएं ग्लूकोज को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। इससे शरीर ऊर्जा के लिए वसा को गलाने लगता है जो बदले में कीटोन्स पैदा करता है। केटोन्स वसा की कमी का कारण बनते हैं। रक्त में कीटोन्स का संचय होने पर वह अम्लीय प्रकृति का हो जाता है और स्थिति बेकाबू हो सकती है। इसी स्थिति को डीकेए कहा जाता है।

रक्त में कीटोन का उच्च स्तर शरीर में जहर पैदा कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज के रोगियों को नियमित रूप से रक्त में कीटोन्स के स्तर की जांच करनी चाहिए। इसे स्वयं बेहद आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए एक स्ट्रिप की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही जैसे प्रेग्नेंसी टेस्ट के लिए आती है। स्ट्रिप पर यूरिन की कुछ बूंदों को डालने पर रंग परिवर्तन आपके कीटोन के स्तर को दशार्ता है। अगर आपको डायबिटीज है और आपको सर्दी या फ्लू है, तो कुछ घंटों के अंतराल में यह परीक्षण करते रहना जरूरी है।

अगर ब्लड शुगर लेवल हाई (240एमजी/डीएल) है, तो आपको हर 4 से 6 घंटे के बाद यह टेस्ट करना चाहिए। डीकेए आपके शरीर में अतिरिक्त डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है, परिधीय भाग में इंसुलिन प्रतिरोध को खराब कर सकता है और काउंटर-रेगुलेटरी हार्मोन में इंसुलिन की मात्रा बढ़ा सकता है।

माह : नवम्बर 2021

राशिफल

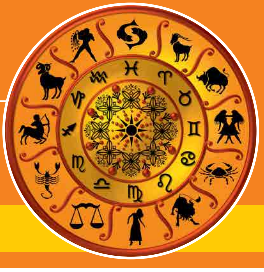

मेष

सूर्य और मंगल की आपकी राशि पर दृष्टि इस माह आपको अनोखे परिणाम प्रदान करेगी। आंतरिक आनन्द बढ़ेगा। उच्च पदस्थ संबंधों से दूरगामी लाभ की बुनियाद बनेगी। प्रथम सप्ताह में आपकी बौद्धिक क्षमता से कोई उलझा काम सुलझेगा। जीवनसाथी का अल्प सानिध्य मिलेगा। अनावश्यक तिकड़म से बचें। वरना अधिक चातुर्य से बात बिगड़ सकती है।

वृष

इस महीने थोड़े प्रयास से बड़े परिणाम मिलेंगे। प्रसन्नता परवान चढ़ेगी। खुशियाँ पल्लवित होगी। ज़िंदगी मुस्कुराएगी। करियर से बेहतर खबर आएगी। सरकारी लोगों की कृपा से लाभ होगा। महीने के पहले हफ़्ते में अचल संपत्ति से लाभ की बुनियाद भी पड़ेगी। कुछ काम बिना सोचे हो जाएँगे और सोच- विचार कर किए गए कुछ काम होते होते रह जाएँगे। या तो लक्ष्य मिलेगा या अनुभव की अनूठी सौगातें मिलेंगी।

मिथुन

शुक्र की आपकी राशि पर सीधी दृष्टि से माह आनंद से सराबोर होगा। नए विचारों के पुष्प पल्लवित होकर आनंद का सृजन करेंगे। कारोबार में बहुत मामूली ही सही, पर गति से संबल मिलेगा। माह के पहले हफ़्ते में सुखद अनुभूतियों का संचार होगा। कमर या पीठ का दर्द महसूस कस सकते हैं। अधिकारों में वृद्धि होगी। करियर और कारोबार में रसूख बढ़ेगा। किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाने से बचें।

कर्क

बृहस्पति की आपकी राशि पर दृष्टि इस माह कमाल करेगी। पर शनि की नजर किसी तनाव का सबब भी बनेगी। जीवनसाथी और स्वयं की सेहत में नरमी के संकेत हैं। अतिउत्साह दिखाने वाली प्रवृति पर नियंत्रण रखें।
सप्ताह के आरंभ में विवेकपूर्ण आचरण से लाभ मिलेगा। सेहत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारी या हल्की दुर्घटना होने की आशंका है।

सिंह

इस माह स्वयं पर विश्वास से आप सफलता का वरण करेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पैनी दृष्टि और आंतरिक गुणों से आपके नाम का झंडा बुलंद होगा। माह के प्रथम सप्ताह में किसी दबाव के अंत के बाद सुकून का सुखद अहसास होगा। करियर में प्रगति होगी, कई मौलिक विचार रंग जमाएंगे। किसी चिर प्रतीक्षित महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने की दिशा में कदम उठाएंगे।

कन्या

आपकी राशि के स्वामी बुध की स्थिति इस माह लाभ का सृजन करेगी। आर्थिक संबल से अंतर्मन में आनंद का अहसास रहेगा। महीने के पहले हफ्ते में शुभ परिणामों की प्राप्ति के आसार हैं। जलने वाले धुआं-धुआं होंगे। माता पिता से संबंध मधुर रहेंगे। पैरों और पीठ में पीड़ा संभव है। किसी पुराने मित्र को कष्ट से मन दुखेगा। सरकार से जुड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मानसिक सुख और दबाव दोनों में वृद्धि होगी।

तुला

शनि की आपकी राशि कर दृष्टि इस माह आपके अधिकार में कुछ कमी करेगी। नकारात्मक चिंतन से मन पर उल्टा असर पड़ेगा। आकस्मिक धन मिलने की उम्मीद बलवती होगी। महीने के प्रथम सप्ताह में बड़ों के आशीर्वाद कई काम बनेंगे। कोशिशें कामयाब होंगी। प्रभाव में वृद्धि होगी। सत्तासीन लोगों से नजदीकियां बढ़ेंगी। प्रतिद्वंदी चारों खाने चित्त होंगे। आर्थिक रूप से यह काल चैन और बेचैनी दोनों देगा।

वृश्चिक

इस माह में किसी आपको आंतरिक खुशी मिलेगी। दर्शन और रहस्य के प्रति रुझान प्रकट होगा। किसी के अत्यधिक मधुर आचरण से उलझन होगी। नवनिर्मित संबंधों से फायदा होगा। महीने के पहले हफ्ते में कारोबार के नए अपरिपक्व विचार तनाव का सबब बनेंगे। नए निवेश में लाभ होगा। आर्थिक रूप से वक्त मध्यम दृष्टिगोचर हो रहा है। किसी पुराने मित्र से अनबन।

धनु

आपकी राशि में शुक्र विराजकर आपको सांसारिक सुख प्रदान कर रहे हैं। महीने के पहले सप्ताह में आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी। हर काम को आप इस बड़े सलीके से करेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। करियर में उत्साहवर्धक परिणाम मिलेंगे। नए उद्यम का अवसर मिलेगा। आपके भाग्य से बहन को लाभ होगा। कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति संभव है। कोई आकांक्षा पूरी होगी।

मकर

यह महीना आपकी शैक्षिक प्रगति व आध्यात्मिक लाभ की कहानी लिख रहा है। कुशल लोगों की संगति से फायदा होगा। महीने के प्रथम सप्ताह में जबरदस्ती बढ़ चढ़ कर आगे दिखने की कोशिश न करें। पीछे रह कर तमाशा देखें। सुख बढ़ेगा। करियर में स्थिति सुदृढ़ होगी। आकस्मिक हानि और लाभ दोनों होंगे। आनन्द और मानसिक दबाव दोनों प्रकार की परिस्थितियाँ रूबरू होंगी। कोई पुराना उलझा मामला और उलझेगा।

कुंभ

यह माह मिश्रित परिस्थितियों से सराबोर रहेगा। कारोबार में उत्साहवर्धक परिणाम मिलेंगे। नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य प्रभावित होगा। मास के पहले हफ्ते में महत्वाकांक्षाएं पूरी होने की राह निकलेगी। किसी मंजे हुए व्यक्ति के अनुभव का लाभ मिलेगा। विचारों के पैनेपन को सराहना मिलेगी। बिना जाँचे-परखे कोई बड़ा कदम न उठाएं। जीवनसाथी से वैचारिक मत भिन्नता संभव है।

मीन

किसी के आचरण से आपका भरोसा दरकेगा। आंतरिक बल में वृद्धि। स्वभाव की उग्रता से में निखार। मानसिक उद्विग्नता। अकस्मात हानि और लाभ दोनों। विवेकपूर्ण आचरण से नुकसान हो सकता है। बुजुर्ग परिजन से संबल मिलेगा। कमर में दर्द या पीठ में अकड़न मुमकिन है। तीसरे हफ़्ते में आपको रूहानी शक्तियों की अनुभूति हो सकती है। संतान की खुशी से सुख प्राप्त होगा।

SWITCH TO ORGANIC

Because Immunity Is What You Eat

ORGALIFE®

ORGANIC STORE

All Product Range Available At Orgalife Exclusive Store

OPP. SHRI RAM MANDIR, SHOP No.15, VIP CHOWK, RAIPUR (C.G.)

For Trade Queries/Suggestions +91-9755188822 care@orgalife.in www.orgalife.in Follow us on